सम्पादकीय

बैंकिंग साख : सरकारी उपक्रम और भुगतान चूक के मामले

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उस समय राहत की सांस साफ सुनी गई, जब बैंकरों को पता चला कि सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की संकट से उबारने की सोच रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों (पीएसयू) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। दूरसंचार और इस्पात मंत्रालय इनके लिए राहत पैकेज पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहे हैं। व्यय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग तथा दूरसंचार विभाग के सचिवों की एक समिति एमटीएनएल के ऋण पर अंतिम फैसला लेगी। 25 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक ने एमटीएनएल को दिया अपना कर्ज गैर निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में डाल दिया क्योंकि 30 जून से ही कंपनी ने किस्त और ब्याज नहीं चुकाए थे। इससे पहले सितंबर के मध्य में ही पंजाब नैशनल बैंक ने भी दूसरे बैंकों की तरह कंपनी के खाते को डाउनग्रेड कर दिया था। स्टेट बैंक ने 1 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंजों के पास एक पत्र भेजा। पत्र के मुताबिक एमटीएनएल के ऋण खाते में 30 सितंबर तक बैंक के कुल 325.52 करोड़ रुपये बकाया थे। एमटीएनएल ने 13 सितंबर को स्टॉक एक्सचैंज को बताया कि उस पर पीएनबी के कुल 441 करोड़ रुपये बकाया हैं और इनमें से 46 करोड़ रुपये वह समय से नहीं चुका पाई है। इससे पहले एमटीएनएल ने यह भी बताया था कि जून और अगस्त 2024 के बीच उसे कई सरकारी बैंकों के 519 करोड़ रुपये चुकाने थे, जो वह नहीं चुका पाई है।

एमटीएनएल सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की 56.25 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम की 13.12 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मार्च 2024 में इसकी नेटवर्थ (हैसियत) 23,663 करोड़ रुपये घट गई थी क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में 2,915.1 करोड़ रुपये का घाटा झेलने के बाद वित्त वर्ष 2024 में भी इसे 3,302 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। उस पर कुल 35,600 करोड़ रुपये के करीब का कर्ज है, जिसमें 27,700 करोड़ रुपये के केंद्र की गारंटी वाले बॉन्ड हैं। इन बॉन्डों की अब भी 'एएए (सीई)' रेटिंग ही चल रही है। सीई का मतलब है कि सरकार की गारंटी मिलने पर कर्ज बढ़ाया गया है। बाकी 7,900 करोड़ रुपये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पीएनबी, पंजाब ऐंड सिंध बैंक और यूको बैंक से सावधि ऋण और पूंजीगत ऋण के तौर पर मिले हैं। आरआईएनएल को विजाग स्टील भी कहा जाता है और उसमें सरकार की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसे वित्त वर्ष 2023 में (नवीनतम ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक) 2,858 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और मार्च 2023 में इसकी नेटवर्थ 391 करोड़ रुपये थी। लेकिन वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में यह नेटवर्थ भी खत्म हो गई क्योंकि कंपनी को 2,058 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। आरआईएनएल पर कुल 20,413 करोड़ रुपये का ऋण है। इसमें 10,812 करोड़ रुपये के सावधि ऋण और 9,601 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी है। एमटीएनएल की तरह ही जून में यह कंपनी भी किस्त और ब्याज चुकाने में नाकाम हो गई, जो सिलसिला अब तक चल रहा है। लगता है कि सभी बैंकों ने सितंबर तिमाही में आरआईएनएल और एमटीएनएल के खातों को फंसे ऋण की श्रेणी में डाल दिया है।

खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश

खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ है। इस प्रतिमा में न्याय की देवी को भारतीय वेषभूषा में दर्शाया गया है। वह साड़ी में दर्शाई गई हैं। सिर पर सुंदर का मुकुट भी है। माथे पर बिंदी, कान और गले में पारंपरिक आभूषण भी नजर आ रहे हैं। जो प्रतीकात्मकता में बदलाव का संकेत है और भारत में न्याय की उभरती भावना को दर्शाता है। लेकिन नई प्रतिमा जिन मूल्यों एवं मानकों की ओर इशारा कर रही है, क्या उसे समझने एवं देखने की हमारी तैयारी है? अगर इस प्रतीकात्मक बदलाव के मूल उद्देश्य को हम नहीं समझ पायेंगे तो यह बदलाव भी अर्थहीन ही होगा।

ललित गर्ग

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय प्रणाली की अनेक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करते हुए अब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। इसके साथ ही मूर्ति की हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह कानून को सर्वदृष्टा एवं भारतीयता का रंग देने की एक सार्थक एवं समयोचित पहल है। सांकेतिक रूप से देखा जाए तो कुछ महीने पहले लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति साफ संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं है और वह संविधान के आधार पर काम करता है। इस सराहनीय कदम के बावजूद एक बड़ा सवाल है कि क्या मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा देने का असर कानूनी प्रक्रिया पर पड़ेगा? भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं, वर्षों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। लेकिन यह स्थिति कब बनेगी? क्या न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन करने से न्याय प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकेगा? निश्चित ही प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ा रही है। लगातार यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं और कानून अब अंधा नहीं है। अब न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में पुस्तक है जो संविधान जैसी दिखती है।

यह सर्वविदित एवं लोगों में आम धारणा है कि थाना-पुलिस और कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगा-लगा कर आम आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है, तब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर भला क्या सुधर जाना है? न्याय की देवी को सच में आंखें देनी हैं तो कानून में आमूल-चूल परिवर्तन, त्वरिता, समयबद्धता एवं समानता की जरूरत होगी। यह तो चीफ जस्टिस भी जानते हैं। आखिर किसे नहीं पता कि इस देश में सड़क से लेकर अदालत तक, हर जगह कानून की धज्जियां उड़ाती हैं और न्याय की देवी पूर्ण ही स्टैच्यू बनी रहती हैं। कोई हरकत नहीं, बिल्कुल संवेदनहीन। सड़कों पर कानून तमाशबीन बनकर खड़ा है, थाने में वह उगाही और उत्पीड़न का अस्त्र बना है तो अदालतों में दलीलों और तारीखों की बेइंतहा उबाऊ प्रक्रिया का जटिल हिस्सा है, जिसकी जकड़न में गए तो खैर नहीं। अब तक अंधे कानून की त्रासदी न्याय की देवी देख नहीं पाती थीं, अब वो खुली आंखों से सब देखेंगी। कम-से-कम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि देख पाने के कारण न्याय की देवी की मूर्ति में भी संवेदना जग जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वाकई अच्छी पहल की है, उसका स्वागत होना चाहिए। 1983 को एक फिल्म अंधा कानून रिलीज हुई थी। इस फिल्म एवं इसके गाने में कोर्ट-कचहरी, वकील-दलील, सुनवाई-फैसले के हालात को शब्द दिए गये हैं। कहा गया कि अस्मतें लुटीं, चली गोली, इसने आंख नहीं खोली। फिर गीत कहता हैं- लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही। पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। इस तरह फिल्म कानून को अंधा बताती है। स्थिति यह है कि आज भी न्यायालयों में यह चर्चा अमूमन होती है कि अदालत में पेश होने वाले अभियोजन या अभियोग पक्ष के रुतबे को देखकर न्याय प्रभावित हो जाता है। लेकिन उस समय की मूर्ति की मूल भावना कहां और कितनी प्रभावी रही है, यह सर्वविदित है। अब नयी संशोधित प्रतिमा का संदेश है कि देश में न्याय अंधा नहीं है, वह इस बात पर जोर देती है कि भारत में न्याय दृरदर्शिता और समानता के साथ काम करता है। जो संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है-यह दर्शाता है कि न्यायालय किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले सभी पक्षों से तथ्यों और तर्कों को तौलता है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसमें न पैसे वाले का महत्व, न रुतबा, ताकत और हैसियत को महत्व दिया जाता है। न्याय की देवी, जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यूनान की देवी हैं। उनका नाम जस्टिया है और उन्हीं के नाम से 'जस्टिस' शब्द आया है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी दिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आजादी के बाद भी हमने इस प्रतीक को अपनाया। यह बदलाव औपनिवेशिक शासन के अवशेषों को हटाने के अन्य प्रयासों को दर्शाता है, भारत गुलामी के सभी संकेतों से बाहर निकलना चाहता है। जैसे कि हाल ही में आपराधिक कानूनों में बदलाव, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करना है। यहां नई मूर्ति के नए संकेतों का अर्थ गहराई से समझना भी जरूरी है। न्याय समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करें, न्यायिक संचालन-प्रक्रिया सांविधानिक प्रावधानों के अनुरूप चले। सबको समान रूप से देखें। हम न्याय की देवी द्वारा इंगित मूल्यों में संजीदगी दिखाये। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर भारतीय न्याय-व्यवस्था को लेकर आम धारणा इतनी कटु क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यहां न्याय देर से मिलता है, जबकि अदालतों में तारीखें अनवरत मिलती रहती हैं? जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की गई है, उसे वास्तविक अर्थों में साकार करने में हम अब तक क्यों विफल रहे हैं? जब तक इन सवालों के उचित जवाब हम नहीं खोज लेते हैं, तब तक न्याय की देवी के प्रतीक-चिह्नों की सार्थकता कठघरे में खड़ी की जाती रहेगी। असल में, प्रतीक-चिह्न एक पहचान के रूप में काम करते हैं। इन प्रतीक-चिह्नों से जो प्रतीकात्मक अर्थ निकल रहा है, वह हर हाल में साकार हो। भारतीय अदालतें इस मामले में उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी हैं। लिहाजा, इन संकेतों के सार्थक होने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। न्याय में देर करना अन्याय है। भारत की न्यायप्रणाली इस मायने में अन्यायपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि भारत की जेलों में 76 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं, जिनका अपराध अभी तय नहीं हुआ है और वे दो दशक से अधिक समय से जेलों में नारकीय जीवन जीते हुए न्याय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए न्यायप्रणाली की धीमी रफ्तार को गति देकर ही ऐसे विचाराधीन कैदियों के साथ न्याय देना संभव है और इसी से सशक्त भारत का निर्माण होगा और प्रतीकात्मक प्रतीक चिह्नों में बदलाव का कोई सार्थक उपयोग एवं असर होगा। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने गौरवपूर्ण इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तंत्र भी स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक, तीक्ष्ण, समयबद्ध और उपयोगी बनाए रखना चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को युक्त करेंगे। तब आप उस जगह पहले है कि आपके जीवन के ऐसे तौरतरीके क्या है, जब आपके जिंदगी बुलंद होंगे और दुनिये सलाम, आपको मिल जाती है लगातार तरक्की होगी। एक ना किसी तरीके सफल में और जीवन खुशी की खुशखबरी एवं व्यवसायक उन्नति की सफलता होगी, क्योंकि पारलौकिक तरीकों से भी, जब एक लगातारता रही सफल और कामयाबी में लक्ष्य प्राप्त होगा

मेष
दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। छुट्टियों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

वृष
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन
यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छुट्टियों में न पड़ें। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

कर्क
विवाद से कलेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे। लेन-देन में लापरवाही न करें।

सिंह
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

कन्या
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक सहयोग मिलेगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आंदोलनव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

तुला
आय में निश्चितता रहेगी। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

वृश्चिक
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी।

धनु
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा।

मकर
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। नौकरीपेशा में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा।

कुंभ
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के मामले मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

मीन
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। स्टोर व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों यदि पत्रकारिता की बात हो रही हो और चन्दन सिंह जी का नाम ना आए,ये हो ही नहीं सकता। अपने व्यवहार से अपनी कमल से आमजन की समस्याओं को शासन-प्रशासन के सामने रखकर उनका निस्तारण करवाने में इनकी बेबाक कलम ने काफी अहम भूमिका निभाई है। इनका जन्म 13 नवम्बर 1976 बाड़मेर में हुआ। पढ़ाई भी बाड़मेर से ही की स्नातक प्रायवेट स्तर पर की वहीं पत्रकारिता दसवी में पढ़ते हुए करना शुरू किया। पहला एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपा । पत्रकारिता का आगाज किया तो फिर तो कलम रूकी ही नहीं। फिर अनेकों समाचार पत्रों में काम किया। सर्व विषय पर लेखन इनकी अद्भुत क्षमता बयां करती है। लोक कला संस्कृति,लोक जीवन,पर्यावरण,वन्य जीव रक्षा जैसे विषयों पर लगातार लेखन। राजस्थानी रत्न ,मारवाड़रत्न ,कथा अलंकरण ,सहित कई सम्मान मिले। जिला स्तर पर लगातार 6 बार सम्मानित,फिर खुद ने सम्मानित के लिए मना किया। जैसलमेर राजपत्रिकार से सम्मानित पत्रकारिता जुनून है शौक है इन्होंने कभी इसे व्यावसायिक नही बनाया। मिशन और मुद्दों पर लेखन प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग हमेशा रहा। सामाजिक कार्यों में कई वर्षों से कार्यरत यही नहीं बाड़मेर जिले की सेक्स वर्कर्स के उत्थान पर प्रशासन के साथ कार्य , 2012 में स्वच्छता अभियान ,परिडे अभियान ,नीम महोत्सव ,चरण पादुका ,गरीबो के लिए क्लॉथ बैंक ,समय- समय पर जरूरतमन्द परिवारों की सहायता। बाड़मेर विकास का सफर नामक पुस्तक का लेखन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साब ने पुस्तक का विमोचन किया व लेखन के लिये प्रोत्साहित किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व उप राष्ट्रपति भैरू सिंह शेखावत भी आपकी पत्रकारिता से खासे प्रभावित रहे

चंदन सिंह भाटी

,बॉर्डर लेखन पर प्रोत्साहन,जातियों में बंटा है सरहद पर पानी जैसी खबर पर बड़े लेखकों व पत्रकारों ने संपादकीय लिखा , इनके आदर्श इनके पिताजी प्रेम सिंह भाटी हैं। बहुत मिलनसार व सभी के साथ मिलकर सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बनाए व बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान टीम पत्रकारिता के ऐसे हीरा का अभिवादन करती है व उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

19 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- बोस्टन में पहली बार आम अदालत का आयोजन 1630 में किया गया।
- फ्रांस के सी. होफर ने 1722 में अग्निशामक यंत्र का पेटेंट कराया।
- इंग्लैंड ने स्पेन पर युद्ध की घोषणा 1739 में की।
- ब्रिटिश जनरल कॉर्नविलास ने अमेरिका में 1781 को आत्मसमर्पण किया, अमेरिकी क्रांति युद्ध का समापन हुआ।
- लैपजिग का युद्ध 1813 को समाप्त हुआ।
- अमेरिका के हवाई प्रांत में 1853 को पहली आटा चक्की शुरू की गयी।
- न्यू साउथ वेल्स में 1872 को विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा (215 किग्रा) पाया गया।
- फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने 1889 में रूस की राजधानी से अपनी सेना हटाई।
- जर्मन वैज्ञानिक मावस प्लांक ने 1900 में 'प्लांक का नियम' प्रतिपादित किया था। इसे 'ब्लैक बॉडी एमिशन' का नियम भी कहा जाता है।
- अब्दुल अजीज ने 1924 में स्वयं को मक्का में पवित्र स्थानों का रक्षक घोषित किया।
- जॉन सी गैरेंड ने 1926 में सेमी ऑटोमेटिक राइफल का पेटेंट कराया।
- ब्रिटिश सरकार ने 1932 को सोवियत संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने 1932 को रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया।
- जर्मनी मित्र राष्ट्रों की संधि से 1933 में बाहर आया।
- रटगर्स विवि के छात्र एल्बर्ट शात्ज ने 1943 को तपेदिक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा 'स्ट्रेप्टोमाइसिन' विकसित की।
- फिलिपीन द्वीप समूह में अमरीका और जापान की सेनाओं के मध्य युद्ध 1944 में आरंभ हुआ।
- मदर टेरेसा ने कलकत्ता (भारत) में मिशनरी ऑफ चैरिटिज की स्थापना 1950 में की।
- श्रीरामुलु पोट्टी ने पृथक् आंध्र राज्य के लिये आमरण अनशन 1952 में शुरु किया।
- रूस और जापान ने हस्ताक्षर कर दोनों देशों के बीच 1945 से चले आ रहे युद्ध को अधिकारिक रूप से 1956 को समाप्त किया।
- नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने वाले अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग-जूनियर को 1960 में अटलांटा में गिरफ्तार किया गया।
- भारत में निर्मित पहला मिग-21 विमान 1970 को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।
- भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डाक्टर एस. चन्द्रशेखर को एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रो. विलियम्स फाउलर के साथ 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।
- न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में 1987 को बिकवाली के भारी दबाव के बीच शेयरों कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर हुआ था।
- जेनेवा में उत्तरी कोरिया और सं.रा. अमेरिका ने 1994 में कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों के प्रसार से मुक्त रखने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत सरकार ने 1834 से 1996 तक सभी केंद्रीय अधिनियमों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार करने की घोषणा 2000 में की।

विशेष आलेख

आधुनिकता से बिखरते परिवार, त्रासदी झेलते बच्चे और बुजुर्ग

संजीव ठाकुर

भारत मूलतः परंपरावादी वैदिक तथा सनातनी देश है पर आधुनिकता ने देश के संयुक्त परिवारों को खंडित कर दिया है। अधिकांश परिवार अब एकल परिवार में परिवर्तित हो गए हैं ऐसे में बुजुर्ग तथा बच्चे सबसे ज्यादा इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। आधुनिक जीवन शैली ने माता पिता को नन्हे बच्चों से दूर कर दिया है इसी तरह बुजुर्गों के साथ उनकी संतानों की संवेदनहीनता ने असहाय सा बना दिया है। बच्चों तथा बुजुर्गों को इसी समय सबसे ज्यादा अपने माता पिता तथा संतानों के सहयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। यदि आधुनिक जीवन शैली के कारण बुजुर्गों तथा बच्चों का उनके अभिभावक एवं पुत्रों पुत्रियों के साथ संवाद होना एक बड़ी पीड़ा का कारण बन जाति है।

भारत में सर्वे के अनुसार बुजुर्गों और नौजवान पीढ़ी के बीच संवाद होना एक चिंताजनक स्वरूप ले चुका हैय बुजुर्ग एकाकीपन से अब मानसिक रोगों के शिकार होने लगे हैं। जिन बुजुर्गों को चलने फिरने और बाहर जाने में परेशानी होती है उनके लिए नौजवान पीढ़ी के साथ संवाद होना परेशानी का एक बड़ा सबक बन चुका हैय महिला तथा पुरुष बुजुर्गों के साथ यह समस्या वृहद रूप लेकर सामाजिक समस्या बन गई हैय बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं इनका जीवन के हर दृष्टिकोण में संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह बच्चों को नैतिक तथा बुनियादी शिक्षा देकर उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी दम पतियों पर होती है पर वर्तमान में बच्चे मां बाप से दूर होते जा रहे हैं और बुजुर्ग अपनी संतानों से मोबाइल ,व्हाट्सएप फेसबुक और इंटरनेट ने नौजवान पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच एक बड़ा संवाद होनता का संकट पैदा कर दिया है। बुजुर्ग यदि अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकेंगे तो उन्हें मानसिक रूप से बीमारी का संकट हो सकता है। नौजवान पीढ़ी को खाली समय में मोबाइल कंप्यूटर में फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए यह संकट और गहराने का खतरा बढ़ता जा रहा हैय उल्लेखनीय है कि बुजुर्गों का अनुभव उनका ज्ञान परिवार,समाज तथा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैय देश की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान और इज्जत उनकी रक्षा निहित हैय करोना की तीसरी लहर से भारतीय समाज में निवास कर रहे बुजुर्गों की बड़ी संख्या को हमें सुरक्षित और महफूज रखना है। वह वटवृक्ष की तरफ हम सबका मार्गदर्शन करते हैं ,अतः हमारा प्रथम कर्तव्य होगा कि हम वृद्धजनों की हर संभव रक्षा कर उनकी इज्जत, तकव्जो करेंय इसके साथ ही हमें बच्चों तथा नौजवानों की भी रक्षा करनी होगीय भारत सरकार की लगातार चेतावनी और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना अभी भी भारत देश में जारी हैय सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैंय हमें कोविड-19 के आतंक के साए को भी नहीं भूलना चाहिए,हमे लगातार सावधानी रख कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाईंस के अनुसार अपना आचरण रखना होगा। अन्यथा कोविड-19 की तीसरी लहर फिर भारत के निवासियों को परेशान कर सकती है। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक हो चुकी है। इसके लिए हमें अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि करोना का केरल हॉटस्पॉट बन चुका है। अब दिल्ली, मुंबई चेन्नई अहमदाबाद तथा पूर्वोत्तर राज्य में भी कोविड-19 की तीसरी लहर के आंकड़े डरावने हो गए हैं। करोना का डेल्टा वैरीअंट यानी करोना की तीसरी लहर हर जगह फैलने लगी है अब यह संक्रमण भारत के महानगरों में फैलने की आशंका को लेकर आया है दिल्ली ,मुंबई कोलकाता, अहमदाबाद,चेन्नई से कोविड-19 की तीसरी लहर अपना पैर पसार चुकी है। और यदि आपने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया, लगातार हाथ नहीं धोया, लोगों से 2 गज की दूरी नहीं रखी और भीड़ भाड़ में जाने से नहीं बचे, तो निश्चित तौर पर कोविड-19 का डेल्टा वैरीअंट को आने से कोई नहीं रोक सकता है । वैसे भी विश्व में इंडोनेशिय,मलेशिया,थाईलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना,अमेरिका में डेल्टा वैरीअंट के तेजी से हजारों प्रकरण बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका डेल्टा वैरीअंट के संक्रमण का भयानक प्रकोप झेल रहा है। भारत में भी पूर्वांचल प्रदेशों में मिजोरम,असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में तीसरी लहर के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका,और फ्रांस जैसे उच्च शिक्षित देशों के नागरिकों ने लॉकडाउन हटते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई गाइडलाईंस का उल्लंघन कर कोविड-19 की तीसरे संक्रमण की लहर को आमंत्रित कर लिया है। अमेरिका के स्वास्थ विभाग के वैज्ञानिक डॉ मूर्ति ने यहां तक कहा कि अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की तीसरी लहर के अल्फा बीटा गामा कप्पा और डेल्टा वैरीअंट से बचने के लिए इंजेक्शन का बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, तभी लोगों की जान बच पाएगी। 24 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश अब तक करोना की लहर से लड़कर उसे दबाने में काफी हद तक सफल रहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्रीयल रोड़ खातीपुरा,निवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालन*। प्रधान संपादक-राय विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 ऑफ कार्यालय-बाईपास निवाई, ऑफ फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का जेहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

अन्याय कहीं का भी हो, लेकिन वह हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। -मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

शराबबंदी के बाद भी

जिस बिहार में बेहद कठोरता से शराबबंदी लागू है, वहां पिछले दिनों गैर-कानूनी ढंग से बनी शराब पीने से हुई मौत के आंकड़े तो स्तब्ध करते ही हैं, इससे यह भी साफ होता है कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार अब भी फल-फूल रहा है और मासूम जानों को भी निगल रहा है। गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 से ही लागू है, लेकिन वहां आए दिन जहरीली शराब की खबरें सुनाई देना वाकई अफसोसनाक है, जिसने वहां की सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। चूंकि 2022 के बाद जहरीली शराब से मरने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है, प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से शराब न पीने की अपील तो कर ही रहे हैं, उन्होंने इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। दरअसल, इस तथ्य को स्वीकारने की जरूरत है कि शराबबंदी कानून को वहां प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं किया जा सका है। यह सच है कि जहां शराब पर प्रतिबंध होगा, वहां गैर-कानूनी ढंग से इसे बनाने की कोशिश होगी ही। हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उन दूसरे राज्यों में, जहां शराबबंदी नहीं है, वहां भी गैर-कानूनी ढंग से बनी शराब पीने से मौतें होती रही हैं। लाजिमी तो यही था कि शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाली नीतीश सरकार गैर-कानूनी ढंग से शराब बनाने और बेचने की व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखती। ऐसा नहीं है, तभी तो शराबबंदी के बाद से बिहार में जहरीली शराब पीने से ढाई सौ से भी ज्यादा लोगों के मरने की बात की जा रही है। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े कम ही मौतों का इशारा करते हैं। जिस तरह से बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में ही है। दूसरी ओर, इन मामलों में अभियोजन की लाचारी का सबूत यह है कि पिछले आठ वर्षों में दोषसिद्धि का आंकड़ा एक फीसदी से भी कम रहा है, कई मामले तो लंबित भी हैं। मौजूदा जासदी पर केंद्रीय मंत्री का यह कहना शोभनीय नहीं है कि 15-16 करोड़

की आबादी वाले राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे मुख्यमंत्री का दो साल पहले का बयान, 'जो पिएगा, वह मरेगा!' बरबस ही जेहन में कौंध जाता है। ऐसे बयान जहरीली शराब जैसे मुद्दे पर सरकारों का अमानवीय रवैया ही दिखाते हैं।

कानून अब अंधा नहीं है?

सजावट के तौर पर रखी गई न्याय-देवी के स्वरूप को न्यायाधीशों की इच्छानुसार बदल दिया गया। लेकिन अंग्रेजी भाषा, सामंती कार्यप्रणाली और आम जनता को तारीखों का रिवाज औपनिवेशिक विरासत से निर्धारित हो रहा है। क्या न्याय-देवी की आंखें खुलने से न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार होंगे?

गुलामी और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने की मुहिम आजादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। इंडिया गेट से जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाना, नई संसद का निर्माण, शहरों और सड़कों का नाम बदलना और तीन नए आपराधिक कानून उस दिशा में प्रयासों को दर्शाते हैं। संविधान निर्माण के 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिह्न का राष्ट्रपति ने अनावरण किया था। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉ. आंबेडकर की मूर्ति की स्थापना के बाद न्यायिक कामकाज का ब्योरा देने वाली न्याय की घड़ी लगाई गई है। उसी कड़ी में न्याय-देवी के स्वरूप में हुए बदलावों को देखा जाना चाहिए।

पिछले साल संविधान दिवस के अवसर पर नई मूर्ति के निर्माण की संकल्पना को केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरा किया है। फाइबर ग्लास से बनी छह फुट की नई मूर्ति में आंखों की पट्टी और हाथ की तलवार को हटा दिया गया है। अब न्याय देवी की आंखें खुली हैं और दाहिने हाथ में तलवार को हटाकर, संविधान सरीखी किताब लगाई गई है। तराजू को बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ में रखने के साथ ही दोनों पलड़े बराबर हैं। नई मूर्ति में भारतीय परंपरा से वस्त्र विन्यास किया गया है।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

प्राचीन रोमन साम्राज्य में जस्टीशिया यानी न्याय की देवी की परंपरा थी। यूनानी साम्राज्य और मध्यकालीन यूरोप में तलवार न्याय का चढ़ा प्रतीक थी। न्याय में तराजू के माध्यम से संतुलन की विरासत मिस्र से मिली। न्याय-देवी में हुए बदलावों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अनेक लोग आंखों की पट्टी खुलने के बाद अंधा युग और अंधा कानून के दौर का खात्मा होने की संभावनाओं से प्रसन्न हैं। न्याय की देवी के प्रतीकों में बदलावों का मकसद न्यायिक व्यवस्था में सुधार है। इसलिए हकीकत से जुड़े अहम सवालों पर सार्थक चर्चा जरूरी है।

आजादी के बाद राजशाही खत्म हो गई और भारत के संविधान में भी सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। परंपरा के तौर पर आंखों में बंद पट्टी को निष्पक्षता से जोड़ा जाता है। इसलिए जजों को छोटे-बड़े, अपने

और पराये में भेद नहीं करके केस का कानून के अनुसार फैसला करना चाहिए। लेकिन हकीकत में यह माना जाता है कि वादकारियों के रसूख और वकीलों के रुतबे यानी फेस लॉ के अनुसार लोगों को न्याय मिलता है। बड़े अपराधी कानून की गिरफ्त में आते नहीं हैं। अगर संयोग से वे गिरफ्तार हो जाएं, तो महंगे वकीलों के दम पर उन्हें जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ लाखों गरीब, अनपढ़ और वंचित वर्ग के लोग जेलों में कैद हैं। आंखों की पट्टी खुलने के बाद क्या गरीबों और आम जनता को जल्द न्याय मिलेगा?

तलवार को हिंसा का प्रतीक मानते हुए उसकी जगह संविधान जैसी किताब लगाई गई है। दंड के बजाय न्याय की बात तीन नए आपराधिक कानूनों में भी की गई है। हजारों अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में पुलिस और अदालती व्यवस्था हजारों निर्दोष लोगों को गिरफ्त में लेकर, बड़े मुजरिमों को रिहा कर देती है। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में पांच करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी के स्वरूप में बदलावों से जिला अदालतों के करोड़ों लंबित मामलों में आम लोगों को कैसे राहत मिलेगी? संविधान में सभी को जल्द न्याय का मौलिक अधिकार हासिल है। क्या नई प्रतिमा के बाद तारीख पे तारीख का रिवाज खत्म हो जाएगा?

संविधान में विकेंद्रीकरण और पंचायती राज पर जोर है। साल 2008 के कानून के अनुसार, देश में ग्राम अदालतों का गठन होना चाहिए। शुरुआत में 2500 अदालतों के गठन की बात थी, जिनमें 500 का गठन हुआ और सिर्फ 314 ही काम कर रही हैं। कर्नाटक में एक मजिस्ट्रेट ने चार वर्षों में सिर्फ 114 मामलों का निपटारा किया। जिला अदालतों और हाईकोर्ट में 25 फीसदी जजों की भर्ती नहीं हो रही, क्योंकि उनके बैठने के लिए कमरे और काम करने के लिए स्टाफ नहीं हैं। राज्यों की सरकारें जिला अदालतों को समुचित संसाधन और बुनियादी तंत्र नहीं दे रहे। कई वर्षों की चर्चा के बावजूद संसद और सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को शुरू नहीं कर पाए। क्या न्याय-देवी की आंखें खुलने के बाद न्यायिक व्यवस्था का रूपांतरण होगा?

राष्ट्रीय पशु, पक्षी और फूल आदि के बारे में कानून की किताबों में जिक्र है, लेकिन न्याय-देवी की प्रतिमा का जिक्र संविधान और कानून में नहीं है। सजावट के तौर पर रखी गई न्याय-देवी के स्वरूप को न्यायाधीशों की इच्छानुसार बदल दिया गया। लेकिन न्यायिक तंत्र को दुरुस्त करने के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं में बदलाव करने के साथ न्यायाधीशों को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा, सामंती कार्यप्रणाली, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां और आम जनता को तारीखों का रिवाज औपनिवेशिक विरासत से निर्धारित हो रहा है। क्या न्याय-देवी की आंखें खुलने से न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार होगा?

जब औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति की बात होती है, तो फिर उनमें घालमेल कर बदलाव करने के बजाय भारतीय प्रतीकों को अंगीकार करने की जरूरत है। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। *रामायण, महाभारत* और कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* में न्यायाधीशों के लिए उच्च आदर्शों का विस्तार से विवरण है। भारतीय इतिहास में न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य भी सर्वाधिक याद किए जाते हैं। हजारों साल बाद भी उनके सिंहासन पर बैठने वालों के ऊपर सत्य और साहस दोनों की छाप दिखती थी। भारतीय परंपरा में भगवान राम के राजा के तौर पर न्याय को आदर्श माना जाता है। जनता के प्रति उनके समर्पण और राजधर्म के अनुशासन की वजह से राम के चरित्र का भारतीय संविधान में चित्रांकन है। उनके आदर्शों पर जज चलें, तो आम जनता से जुड़ने के साथ परिवारवाद से दूर रहने का संकल्प लेना होगा। इतिहास में गए बगैर आधुनिक काल में प्रेमचंद की कहानी *पंच परमेश्वर* के नैतिक आदर्शों से प्रेरणा लेकर जज आम जनता को समय पर और सही न्याय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 70 हजार मुकदमों के लिए न्याय की घड़ी की स्थापना के बाद देश भर में पांच करोड़ मुकदमों और विचाराधीन कैदियों का नवीनतम विवरण देने वाली न्याय की घड़ी की स्थापना की जाए, तो न्याय-देवी में हुए सजावटी बदलाव पूरे देश की जनता के लिए सार्थक हो सकते हैं।

edit@amarujala.com

सामरिक

सिनवार की मौत ने खोली उम्मीदों की राह

हमास नेता की मौत से गाजा युद्ध को समाप्त करने, इस्राइली बंधकों को वापस लाने और गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने की संभावना पैदा होती है। इससे इस्राइल और फलस्तीनियों के बीच द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में कदम उठने की उम्मीद भी बंधती है।

हमास नेता याह्या सिनवार की मौत से न केवल गाजा युद्ध को समाप्त करने, इस्राइली बंधकों को वापस लाने और गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने की संभावना पैदा होती है, बल्कि इससे इस्राइल और फलस्तीनियों के बीच द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में कदम उठने की उम्मीदें भी बलवती होती हैं। यही नहीं, इससे इस्राइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की राह भी खुलती दिखती है। हालांकि, सिर्फ सिनवार की मौत गाजा युद्ध खत्म करने और इस्राइल व फलस्तीनियों को बेहतर भविष्य की राह पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसा होना जरूरी था। अब जरूरत इस बात की है कि इस्राइल सिनवार की मौत से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाए।

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय शांति सेना में परिपक्व वेस्ट बैंक फलस्तीनी प्राधिकरण की भागीदारी को स्वीकार करना होगा, जो सिनवार के नेतृत्व वाले हमास के स्थान पर गाजा पर कब्जा करेगी। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, पिछले एक महीने से राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के निर्देश पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण के लिए क्या किया जाए। व्यापक विचार यह है कि फलस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नए पूर्व फलस्तीनी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने पर सहमत किया जाए, जो प्राधिकरण में सुधार लाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे तथा इसके प्रशासन और सुरक्षा बलों को उन्नत करेंगे। इस तरह सुधरा हुआ फलस्तीनी प्राधिकरण औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की मांग करेगा। इस बल को गाजा में इस्राइली सेना की जगह लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा। फिर प्राधिकरण विभिन्न देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए राहत कोष से गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, नेतन्याहू समझते हैं कि अरब, गाजा में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए अरब/अंतरराष्ट्रीय शांति सेना में तभी भाग लेगा, जब वह फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

थॉमस एल. फ्रीडमैन

बता दें कि इस तरह से युद्ध को समाप्त करने के लिए अंततः फलस्तीनी देश बनाने के लिए इस्राइल की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी, जिसका नेतन्याहू के अतिवादी दक्षिणपंथी सहयोगी सख्त विरोध कर सकते हैं। वे सिनवार की हत्या और हमास के पतन को एक अवसर के रूप में देखेंगे, ताकि वे गाजा में यहूदी बस्तियां बसाने और वेस्ट बैंक में उनका विस्तार करने के अपने एजेंडे को पूरा कर सकें। अब देखना है कि नेतन्याहू इतिहास बदलने के लिए बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। लेकिन यह मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। अगर वह अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया को बाइडन के राष्ट्रपति रहते शुरू किया जाना चाहिए। लंबे समय से पश्चिम एशिया की उथल-पुथल को कवर करने वाले पत्रकार के रूप में मुझे उम्मीद है कि गाजा के फलस्तीनियों की हत्या बंद हो जाएगी, बंधकों को वापस कर दिया जाएगा और वास्तविक कूटनीति शुरू हो जाएगी। और अगर संबंधित नेता अभी तैयार होते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है।

©The New York Times 2024

तकनीकी क्रांतियों से नौकरियों का नुकसान पहले भी हुआ है। लेकिन नई नौकरियां पैदा होती हैं। एआई क्रांति के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। - राम मुखर्जी

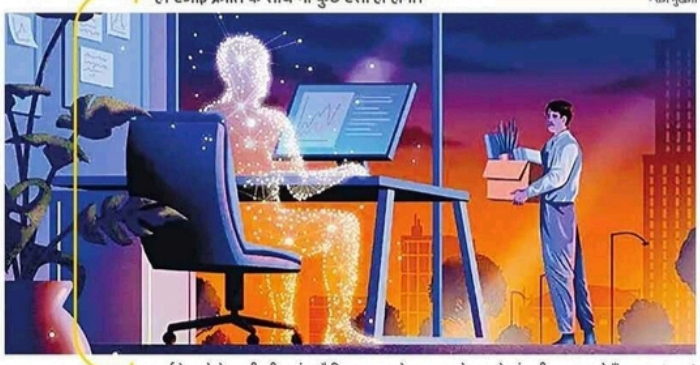

एआई के आने से इसकी पूरी आशंका है कि हम मनुष्य के प्रभुत्व वाले काल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। -युवाल नोआ हरारी

मन सच्ची प्रयोगशाला, जहां छिपा है सत्य

विज्ञान के आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के बिना दुनिया के आश्चर्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है। ज्ञान ने ही मुझे प्रकृति की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है, जो लंबे समय से संवादहीन थी। विज्ञान हमारे समय की सबसे बड़ी रचनात्मक प्रेरणा है।

मेरी शिक्षा कैंब्रिज में हुई। मुझे लगता है कि शिक्षा केवल वह जानकारी नहीं है, जो मस्तिष्क में भर दी जाती है, जो जीवन भर अनियंत्रित रूप से मस्तिष्क में घूमते रहती है। जीवन-निर्माण, मानव-निर्माण, चरित्र-निर्माण के विचारों को आत्मसात करना शिक्षा का सही उद्देश्य है। विज्ञान के आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के बिना दुनिया के आश्चर्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा ने ही मुझे प्रकृति की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है, जो लंबे समय से संवादहीन थी। मेरा क्रेस्कोग्राफ (पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण) पर इसका सबूत है कि पौधों में भी एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र और विविध भावनात्मक जीवन होता है, जो प्यार, नफरत, खुशी, डर, दर्द, स्तब्धता, और उत्तेजनाओं के लिए पौधों में अनगिनत उचित प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है।

जगदीश चंद्र बोस

हम अक्सर विज्ञान और वैज्ञानिकों को कठोर, दिमागी व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, जो प्रक्रिया, परिभाषा और परिणाम से जुड़े होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा और प्रेम के बगैर विज्ञान का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। दरअसल, सच्ची प्रयोगशाला मन है, जहां हम भ्रम के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोजते हैं। विज्ञान हमारे जीवन को आकार देता है, न केवल उन भौतिक चीजों में, जो इसने हमें आज तक दी है, बल्कि इस मायने में भी कि यह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। रोमांच का कोई अंत नहीं है, यहां हम कुछ भी नया ढूंढ सकते हैं, बस हमें अपनी आंखें खोलकर तलाशना होगा।

जीवन धारा

हमें प्रकृति के नियमों को समझने के लिए किसी दूरबीन की आवश्यकता नहीं है, केवल जागृत मन की आवश्यकता है। इस जागृत मन की कमी का ही परिणाम है कि विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के अनुप्रयोगों का दोहन करने की तीव्र होड़ मची हुई है, जो अक्सर बचाने के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए होती है। संयम शक्ति के अभाव में, सभ्यता बर्बादी के कगार पर अस्थिर होकर कांप रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपने जीवन में उच्च उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान को जीतने और सत्य को आमने-सामने देखने और जीवन के अनंत संघर्षों में स्वयं को समर्पित करेंगे, क्योंकि जीवन और कुछ नहीं बल्कि मन का विकास है।

एआई मेरी बिल्ली पर कहानी नहीं लिख सकता

जैसे मोटरगाड़ियों ने घोड़ा गाड़ियों की जगह ली, एआई भी पुरानी तकनीकों को बदलेगा। पर वह कभी मेरी मर चुकी बिल्ली पर कहानी नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी यादें मेरी कल्पना के 'क्लाउड' में बसती हैं।

डेविड मीन्स
कहानीकार

एक बिल्ली मुझे बहुत प्यारी थी, जो कई वर्षों तक मेरे परिवार का हिस्सा बन कर रही। मुझे आज भी उसका अंतिम दिन याद है। वह दर्द में थी, जिसे मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। कई वर्ष बीत जाने के बाद मेरे दिमाग में अपनी उसी बिल्ली पर एक कहानी लिखने का ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद ली जाए। एआई ने कहानियां लिखीं, लेकिन मुझे लगा कि एआई कभी मेरी बिल्ली पर कहानी नहीं लिख सकता, क्योंकि वह बिल्ली मेरी कल्पनाओं में है या फिर उन शब्दों में, जिन्हें मैंने तब लिखा था, जब मैं बोस्टन में अपनी बेटी के घर में गर्मी के एक दिन बैठा हुआ था।

बिल्ली को लेकर मेरी यादें और मेरे शब्द चूंकि इंटरनेट की दुनिया में नहीं हैं, इसलिए एआई की पहुंच से भी बाहर हैं। अगर मैं अपनी इस कहानी को प्रकाशित करवाता हूं, तो कौन जाने शायद कोई मशीन इसे अपने में खींच ले और मानवीय सरोकारों से उपजी मेरी शैली, मेरे शब्द, मेरे प्रेम और मेरी निराशा को मशीन में डालकर क्या से क्या बना डाले। फिलहाल मैंने कहानी पूरी लिखी नहीं है, लेकिन यह मेरी कल्पना में महफूज है। मशीन इसकी नकल नहीं कर सकती। मशीन इसलिए कह रहा हूं कि एआई एक मशीन ही तो है। क्या यह उस पीड़ा को महसूस कर सकती है, जो अपने पिता की मृत्यु पर अपने गृह नगर जाते वक्त मुझे हुई थी। पिता के उन आखिरी संस्कारों के अनुभवों ने मुझे याद दिलाया कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और मेरी लिखी किताबें यहीं छूट जाएंगी। मैं एआई से प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाला हूं या यह बहस नहीं करने वाला हूं कि यह तकनीक कलाकृति की नकल कर सकती है या कला के निर्माण में मनुष्यों की सहायता करती है, लेकिन मैं अभी यह जरूर कह सकता हूं कि एआई वह कभी नहीं कर पाएगा, जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि एआई ने कभी वह महसूस नहीं किया, जो मैंने किया है। यह कभी सांचों से आगे नहीं बढ़ पाएगा।

स्मृतियां समय के साथ छनती, परखी व बदलती जाती हैं और कोई भी मशीन उस दर्द को महसूस नहीं करती, जो कहानी के केंद्र में है, जिसे रचने के लिए मैं संघर्ष करता हूं। एआई को कभी उस नश्वरता का अनुभव नहीं होगा, जो एक आधे-अधूरे प्राणु के इर्द-गिर्द बुनी जाती है। मानवीय स्थिति की अतार्किकता व विरोधाभास, और दर्द व खुशी का वह ब्रह्मांडीय एकीकरण, जो एक कृति पर तब तक काम करते रहने के लिए कलात्मक रूप से प्रेरित करता है, जब तक कि वह पूरी न हो जाए और पूरी तरह कलाकार की न हो जाए, क्या एआई कला और कलाकार के इस जुड़ाव को समझ सकता है।

कोई भी मशीन उस भय और उल्लास को महसूस नहीं कर सकती, जो मैंने तब महसूस किया, जब मैं अस्पताल के गलियारे में अपने जुड़वां बच्चों को तौलिये में लपेटे हुए अकेला खड़ा था, पहली बार आंखों से संपर्क स्थापित करते हुए और एक अलग तरह के अकेलेपन, जिम्मेदारी और प्यार को महसूस करते हुए। मौलिकता उस विचार या एहसास में निहित है, जो दिमाग में बिजली की तरह एकाएक कौंधता है। जैसे मोटरगाड़ियों ने घोड़ा गाड़ियों की जगह ली, एआई भी पुरानी तकनीकों को बदलेगा, नए आयाम गढ़ेगा। लेकिन हम कलाकार वही करेंगे, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। मानवता पर दावा करने के लिए नए तरीकों की खोज करना। इसके लिए वह किताबें लिखेगा, तस्वीरें बनाएगा, संगीत की रचना करेगा, नक्काशी करेगा और वह सब कुछ करेगा, जिसके लिए उसे अनजानी कल्पनाओं के अनंत जगत में गोते लगाना पड़े। क्या एआई इतनी मशक्कत करेगा?

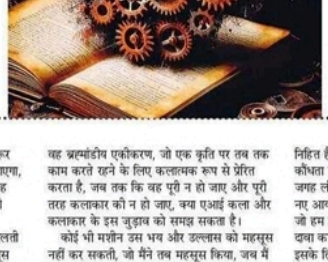

एक्सप्लेनेबल इनसाइट

एक्सप्लेनेबल इंटेलिजेंस एआई ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नई सुविधा है, जो एक एल्गोरिदम का उपयोग करके जटिल बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराती है। यानी इससे मिलने वाली जानकारी का उपयोग करने से एआई को निर्णय लेने में सहूलियत होती है। इसका निर्माण एआई और मशीन लर्निंग की अवधारणाओं पर किया गया है।

एक्सप्लेनेबल एआई

एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एक्सएआई) प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का एक तंत्र है, जो इंसानी उपयोगकर्ताओं को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा बनाए गए परिणामों और उत्पादों को समझने तथा उन पर भरोसा करने की अनुमति प्रदान करता है। एक्सएआई का उपयोग एक एआई मॉडल से अपेक्षित प्रभाव और संभावित पूर्वाग्रहों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह एआई संचालित निर्णय लेने में मॉडल सटीकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और परिणामों को चित्रित करने में मदद करता है। एक्सएआई किसी संगठन को एआई विकास के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद करता है।

©The New York Times 2024

चिंतन

परंपरा की आड़ में बाल विवाह कानूनन गलत

बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट राय देकर सभी समुदाय की नाबालिग लड़कियों को रक्षा की है। धर्म, संस्कृति व परंपरा की आड़ में अनेक समुदाय अपनी नाबालिग लड़कियों की शादी कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दो टूक कहा है कि किसी 'पर्सनल लॉ' के तहत परंपराएं बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा नहीं बन सकतीं और बचपन में कराए गए विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। यूं तो सरकारी जागरूकता और कठोर कानून के चलते देश में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी कई समुदाय परंपरा की आड़ में इस कानून का उल्लंघन करते हैं। देश में वर्ष 1993 में बाल विवाह के मामले 49 फीसदी थे, जो वर्ष 2021 में घटकर 22 फीसदी रह गए, वर्तमान में यह 20 फीसदी के लगभग हैं। बाल विवाह की सबसे अधिक शिकार बालिकाएं बनती हैं। वर्ष 2006 में बालकों के बाल विवाह के केस 7 फीसदी थे, जो वर्ष 2021 में घटकर 2 फीसदी रह गए, अभी यह दो फीसदी से कम है। वर्ष 2005-2006 से 2015-2016 के बीच 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 47 फीसदी से घटकर 27 फीसदी रह गई, लेकिन आंकड़े फिर भी ज्यादा हैं। बाल विवाह के मामलों में सज्जा की दर सिर्फ 11 फीसदी है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 2022 में बाल विवाह मुक्त भारत आंदोलन की शुरुआत की थी, इस आंदोलन का मकसद वर्ष 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करना है, लेकिन धर्म संस्कृति की आड़ में बाल विवाह होते रहने के चलते यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा है। यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष, 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती है, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 वर्ष की उम्र की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां शादीशुदा हैं। यूनिसेफ के अनुसार किसी लड़की या लड़के की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। भारत में धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक परंपराएं, अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक दबाव, जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य जनित खतरे के बारे में नहीं पता होना, कानून के प्रति सम्मान का भाव नहीं होना, कानूनों के क्रियान्वयन में कमी आदि बाल विवाह के कारण हैं। बाल विवाह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा में बाधा, घरेलू हिंसा का शिकार होना, गरीबी का दुष्चक्र आदि दुष्परिणाम होते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिए किसी भी पर्सनल लॉ को खारिज कर बाल विवाह रोकथाम कानून की श्रेष्ठता को स्थापित राहत दी है। अब जो लोग पर्सनल लॉ के नाम पर कानून का उल्लंघन कर रहे थे, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई हो सकेगी। देश में हर समुदाय, समाज, धर्म व संस्कृति के लोगों के लिए बाल विवाह रोकने के कानून का पालन करना अनिवार्य है। केन्द्र सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय से बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को 'पसर्नल लॉ' पर प्रभावी बनाए रखने का आग्रह किया था। सरकार, कानून, सामाजिक संगठन आदि सभी की चाहत है कि देश में बाल विवाह न हो, नाबालिगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार न छीने जाएं। बाल विवाह मुक्त समाज विकसित भारत के लक्ष्य के लिए भी जरूरी है।

ऐसे ही नहीं है टाटा के प्रति दीवानगी

उत्तराधिकारी
प्रदीप सरदाना

> रतन टाटा भारत के सच्चे रत्न थे। उन जैसा कोई और नहीं। जबकि सामान्यतः उद्योगपतियों के प्रति लोगों का नज़रिया कुछ अच्छा नहीं होता। कितने ही लोग बहुत से उद्योगपतियों के बारे में कहते हैं कि वे आम लोगों को लूट खसोट कर ही अमीर बने हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब देश में किसी उद्योगपति को देवता सा बना दिया है। देश में विपक्ष के कुछ बड़े नेता तक आए दिन अंबानी-अडानी को कोसते नहीं थकते। लेकिन विपक्ष ने भी कभी टाटा को नहीं कोसा। इधर, अब जब रतन टाटा के साम्राज्य की बागडोर उनके सौतेले भाई 67 वर्षीय नोएल टाटा के हाथों में आ गयी है तो सवाल ये है कि क्या नोएल, रतन टाटा जैसे आदर्श स्थापित कर पाएंगे?

उद्योगपति रतन टाटा को इस दुनिया से विदा हुए करीब 10 दिन हो गए हैं लेकिन उनके प्रति लोगों की दीवानगी थमने का नाम नहीं ले रही। जिसे देखो वह रतन टाटा की सादगी और महानता का जमकर गुणगान कर रहा है। बड़ी बात यह भी कि इन गुणगान करने वाले लोगों में अधिकांश का कभी रतन टाटा से मिलना तो दूर, उन्हें दूर से देखना तक नहीं हुआ। फिर भी सभी एक सुर में बोल रहे हैं, रतन टाटा भारत के सच्चे रत्न थे। उन जैसा कोई और नहीं। जबकि सामान्यतः उद्योगपतियों के प्रति लोगों का नजरिया कुछ अच्छा नहीं होता। कितने ही लोग बहुत से उद्योगपतियों के बारे में कहते हैं कि वे आम लोगों को लूट खसोट कर ही अमीर बने हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब देश में किसी उद्योगपति को देवता सा बना दिया है। देश में विपक्ष के कुछ बड़े नेता तक आए दिन अंबानी-अडानी को कोसते नहीं थकते। लेकिन विपक्ष ने भी कभी टाटा को नहीं कोसा। इधर, अब जब रतन टाटा के साम्राज्य की बागडोर उनके सौतेले भाई 67 वर्षीय नोएल टाटा के हाथों में आ गयी है तो सवाल ये है कि क्या नोएल, रतन टाटा जैसे आदर्श स्थापित कर पाएंगे? क्या वह टाटा के महासाम्राज्य को संभालने के साथ टाटा की नैतिक और परोपकारी विरासत को भी संभाल सकेंगे?

असल में ये सवाल तब भी उठे थे जब 31 बरस पहले जेआरडी टाटा का निधन हुआ था। हालांकि जेआरडी अपने निधन से दो वर्ष पूर्व ही स्वयं रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे। लेकिन रतन टाटा का नाम सुर्खियों में तभी आया, जब 29 नवंबर 1993 को जेआरडी का निधन हुआ। तब तक जेआरडी ऐसे ही विख्यात थे जैसे अब रतन हैं। मैंने तब जेआरडी पर अपने लेख में लिखा था -'रतन टाटा जेआरडी के साम्राज्य को कैसे संभालते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जेआरडी की बुलंदियों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है।' लेकिन रतन टाटा ने पिछले 30 बरसों में जेआरडी की सादगी और नैतिकता के साथ उनकी दूरदृष्टिता और बुद्धिमता को भी कुछ ऐसे अपनाया कि कुछ मामलों में वह उनसे भी आगे निकल गए। असल में रतन टाटा ने टाटा की बुलंदियों को तो नया शिखर दिया ही, अपने व्यवहार और कार्यों से सभी का दिल भी जीता। लेकिन अनेक मामलों में रतन ने जेआरडी का अनुसरण किया। मुझे भी जेआरडी टाटा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि सादगी जैसे कुछ मामलों में जेआरडी, रतन टाटा से भी आगे थे। टाटा समूह के होटल ताज विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन ताज होटल की विशाल श्रंखला के प्रमुख जेआरडी का भारत में अपना कोई एक घर तक नहीं था। हालांकि पहले मुंबई में उनका एक अपार्टमेंट था। लेकिन जेआरडी ने उसे बेचकर महिलाओं के विकास और कल्याणार्थ 'थेलमा जेआरडी ट्रस्ट फॉर द वीमेंस डेवलेपमेंट' बना दिया था। यहां तक वह अकेले या अपनी पत्नी थेलमा के साथ दिल्ली या किसी अन्य शहर में जाते तो वहां अपने ताज होटल में आने से पहले कोई विशिष्ट कमरा आरक्षित करने का निर्देश नहीं देते थे। वहां पहुंचने पर होटल में तब चाहे कोई छोटा कमरा उपलब्ध हो तो वे उसमें सहजता से ठहर जाते थे। जेआरडी से जब एक बार उनसे अपना भारत में घर न होने के बारे में पूछा तो उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा था-'मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा

करों में निकल जाता है। इसलिए घर बनाने के लिए पैसे बचते ही नहीं।' इधर कुछ लोग समझते हैं कि मुंबई का भव्य होटल ताजमहल जेआरडी ने बनाया था। लेकिन देश के इस पहले पंचतारा होटल को टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने 1903 में बनाया था। जबकि जेआरडी का जन्म इस होटल के शुरू होने के बाद 29 जुलाई 1904 को हुआ था।

मुझे जेआरडी से कुछ अधिक प्रेम इसलिए भी रहा कि इन महान हस्ती और मेरी जन्म तिथि एक ही है। जेआरडी ने अपने पूर्ववर्ती सर नौरोजी सकलातवाला के निधन के बाद 1938 में टाटा समूह की कमान संभाली थी। करीब 53 बरस तक टाटा संस के चेयरमैन रहकर जेआरडी ने टाटा समूह को एक नया शिखर दिया। देश स्वतंत्र होने के बाद वे ही टाटा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में नित नए उद्योगों की मजबूत नींव रख, भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाई। टाटा की 14 कंपनियों को बढ़ाते हुए वह 95 कंपनियों तक ले गए। साथ ही देश में नागरिक विमानन सेवा की शुरुआत भी उन्होंने की। भारत में उड़ान का लाइसेंस पाने वाले वह पहले पायलट थे। जेआरडी ने टाटा समूह का प्रमुख बनने से पूर्व 15 अक्टूबर 1932 को कराची से मुंबई की अपनी 'टाटा एयर लाईस' से उड़ान भर, देश में नागरिक उड्डयन का नया अध्याय लिख दिया था। फिर 1948 में 'टाटा एअरलाईस' को एअर इंडिया बना दिया गया। साथ ही जेआरडी ने दिल्ली के दोनों ताज होटल सहित विश्व भर में 37 ताज होटल स्वयं बनाए।

यहां तक कि परमाणु ऊर्जा और परिवार नियोजन के लिए भी जेआरडी ने बहुत काम किया। जेआरडी का कद कितना बड़ा था, उसे इससे भी समझा जा सकता है कि अभी तक देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 53 व्यक्तियों में, उद्योगपति एक ही हैं-जेआरडी टाटा। इसलिए जब जेआरडी का निधन हुआ तो तब भी देश उन्हें ऐसे नमन कर रहा था,जैसे अब रतन टाटा को किया जा रहा है। जेआरडी ने अपने आचरण और मर्यादाओं से जो श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित किए, उसी मार्ग को रतन टाटा ने अपनाकर, टाटा समूह को शीर्ष सोपान पर पहुंचाया। इसलिए कुछ बरसों से रतन टाटा को भी भारत रत्न देने की मांग लगातार उठ रही है। देखा जाए तो सन 1868 में जमशेदजी द्वारा स्थापित टाटा समूह की आदर्श विरासत लगातार चली आ रही है। जमशेदजी के बाद सर दोराबजी टाटा ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और फिर नौरोजी सकलातवाला, जेआरडी और रतन टाटा ने। रतन टाटा ने अपने कुशल प्रबंधन से टाटा समूह के उत्पादनों को घर-घर का हिस्सा बना दिया। वहीं जीवन में चार बार विवाह के मौके बनने के बाद भी उन्होंने अपना घर नहीं बसाया। वह आजन्म अविवाहित रहे। लेकिन अपने टाटा समूह के हर कर्मचारी को अपने परिवार का सदस्य मान, वे सभी के सुख-दुख में साथ खड़े रहे। यहां तक कि देश और समाज के लिए वह अपना योगदान देने के लिए सदा तत्पर रहे। यदि रतन टाटा चाहते तो वह भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन सकते थे। लेकिन उन्होंने धन को महत्व न दे नैतिकता, प्रतिष्ठता, ईमानदारी और परोपकारिता पर बल दिया। आज तभी सभी सबसे ज्यादा भरोसा टाटा उत्पादनों पर करते हैं। रतन टाटा ने ऐसी कई बड़ी मिसाल कायम की, जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुकी हैं। उसी पुराने इतिहास और आदर्श परम्पराओं को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि पिछले 40 बरसों से टाटा संग जुड़े नोएल टाटा भी, टाटा की समृद्ध और आदर्श विरासत को बनाए रखेंगे। बता दें कि नोएल टाटा की शादी स्वर्गीय पल्लोनजी मिस्त्री की बेटी और स्वर्गीय साइरस मिस्त्री की बहन अलू मिस्त्री से हुई है। इनके तीन बच्चे हैं: बेटियां लीया और माया, और बेटा नॉवेल।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

नोएल का उदय

विवेक शुक्ला

टाटा-मिस्त्री परिवारों में सुलह की संभावना

रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को पिछले शुक्रवार को शक्तिशाली टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद मेहली मिस्त्री के टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। मिस्त्री को टाटा समूह के स्वर्गीय अध्यक्ष एमेरिटस, रतन टाटा का करीबी विश्वासपात्र माना जाता था। रतन टाटा के निधन के बाद, भारत की कारपोरेट दुनिया और सत्ता के गलियारों में यह अफवाह जोरों पर थी कि मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट के प्रमुख बनने जा रहे हैं। मेहली मिस्त्री, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, स्वर्गीय साइरस मिस्त्री की मौसी के पुत्र हैं। यानी दोनों चचेरे भाई हैं। मेहरजी पल्लोनजी ग्रुप के निदेशक, मेहली मिस्त्री को नवंबर 2022 में सर रतन टाटा ट्रस्ट, इसके सहयोगी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के गैर-कार्यकारी ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। वे दिन थे जब रतन टाटा का टाटा ट्रस्ट्स में दबदबा था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के अध्यक्ष पद से हटाने के समय मेहली मिस्त्री रतन टाटा का पूरी तरह से साथ दे रहे थे। रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच हुए कटु विवाद ने मीडिया का खूब ध्यान खींचा था। टाटा समूह के जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में ट्रस्ट्स में मेहली मिस्त्री की भूमिका काफी बढ़ गई थी। इसलिए, टाटा ट्रस्ट्स का प्रमुख बनने के लिए उनका नाम चर्चा में था। टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे होने के बावजूद, मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट्स का प्रमुख नहीं बन पाए। कहा जाता है कि नोएल टाटा को सर्वसम्मति से शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा की एक सफल और गैर-विवादास्पद व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठा ने टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख के रूप में उनके चयन में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने टाटा इंटरनेशनल में अपना करियर शुरू किया था। वे जून 1999 में, टाटा व समूह की खुदरा शाखा ट्रेंट के प्रबंध निदेशक बने, जिसकी स्थापना उनकी मां सिमोन टाटा ने की थी। इस समय तक ट्रेंट ने पिटार्डमेंटल स्टोर लिटिलवुड्स इंटरनेशनल का अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम बदलकर वेस्टसाइड कर दिया था। उन्होंने वेस्टसाइड को विकसित किया, इसे एक लाभदायक उपक्रम बनाया। 2003 में, उन्हें टाइटन इंडस्ट्रीज और वोल्तास का निदेशक नियुक्त किया गया। दूसरी ओर, मेहली मिस्त्री व्यावसायिक सौदों में कुछ गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे। एक प्रमुख विवाद मेहली मिस्त्री के टाटा पावर के साथ व्यावसायिक सौदों से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उनकी कंपनी को टाटा पावर द्वारा उचित निविदा प्रक्रिया के बिना आकर्षक दीर्घकालिक अनुबंध दिए गए थे। हालांकि, मेहली मिस्त्री ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया है। यहां तक कि टाटा संस ने भी इस आरोप का खंडन किया है कि मेहली मिस्त्री और उनके सहयोगियों को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना टाटा पावर द्वारा दिए गए अनुबंधों से लाभ हुआ। मेहली मिस्त्री मेहरजी पल्लोनजी ग्रुप के निदेशक रहे हैं। इस बीच, मेहली मिस्त्री कहते रहे हैं कि उन पर लगाया गया आरोप कि वह साइरस मिस्त्री को टाटा संस के प्रमुख पद से हटाने के पीछे थे, असत्य है। बता दें कि साइरस मिस्त्री का परिवार, अपनी होल्डिंग कंपनी शापूरजी पल्लोनजी के माध्यम से, टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी रखता है, जो उन्हें टाटा ट्रस्ट्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनाता है। खैर, मेहली मिस्त्री और साइरस मिस्त्री के बीच का झगड़ा सिर्फ एक निजी विवाद नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक और कानूनी लड़ाई थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक मुकदमेबाजी हुई। मेहली खुलकर रतन टाटा का साथ देते रहे थे। क्या उस विवाद में मेहली मिस्त्री की कथित भूमिका के चलते उन्हें टाटा ट्रस्ट्स को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला? यह सवाल अभी बना हुआ है। उस विवाद के कारण मेहली मिस्त्री और साइरस मिस्त्री के परिवारों में दूरियां भी बढ़ी थीं। अब जब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं, तो टाटा-मिस्त्री परिवार के भीतर सुलह के एक नए अध्याय की शुरुआत होने की उम्मीद है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि नोएल टाटा के सक्षम नेतृत्व के चलते टाटा और मिस्त्री परिवार के बीच संबंध सुधरने लगेंगे। टाटा समूह में मेहली मिस्त्री के भविष्य की भूमिका पर सवालिया निशान है, बावजूद इसके कि रतन टाटा के साथ उनके गहरे संबंध थे। टाटा समूह के जानकारों का कहना है कि वे निश्चित रूप से टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करने की क्षमताएं नहीं रखते। बहरहाल, टाटा समूह नोएल टाटा के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना खास रोल निभाता रहेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हृदय का करें अनुसरण

संकलित
दर्शन

कोई भी धर्मग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्मग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हम सारी उम्र धर्म या ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। दुनिया के विद्वानों ने भले ही हमारी बुद्धि प्रखर कर दी हो, पर हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सके। पाश्चात्य संस्कृति का दोष यह है कि हम बुद्धि का संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य दस गुना स्वार्थी हो जाता है। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो, तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती, पर वह केवल हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय, बुद्धि का अतिक्रमण कर अंतःस्फूर्ति को पा लेती है। बुद्धि से कभी अंतःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोदय वासित हृदय ही है। बुद्धिप्रधान, किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंतःस्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय अंतःस्फूर्ति का। शुरुआत में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता, जितनी कि बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वह थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है।

प्रार्थना के बाद भी भगवान नहीं सुन रहे?

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ के घर के बाहर एक साधू महाराज खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और बदले में खाने को रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूं। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूं। साधू ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और रोटी मांग रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था, आखिर सेठानी से बोला- रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहे हैं, उन्हें कह रही हो आ रही हूं तो उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली- हाँ रोटी दूँगी, पर क्या है ना कि मुझे उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है, अगर उनको रोटी दे दूँगी तो वो आगे चले जायेंगे। मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है, इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुःख और कष्ट आए पर प्रार्थना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना? फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़ियें। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

मोदी के सत्ता में रहते हुए 23 साल पूरे

पहले गुजरात के सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते अपने सत्ताधारी के रूप में 23 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति के गलियारे से निकलकर दिल्ली की राजनीति तक पहुंचे हैं और वह कई बार गुजरात जाकर वहां के विकास कार्यों पर भी नजर रखते हैं। इस कारण गुजरात भी प्रधानमंत्री पर विश्वास रखता है और भाजपा के पक्ष में मतदान करता है। इसके बेहतर और जबरिहत-देसहित के कामों के प्रति साफ नीयत पर देश ने भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के शायद पहले ऐसे लेता हैं, जिन्होंने भाजपा को प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होकर एक नई पहचान दी है। देश ने इन पर भरोसा कर तीसरी बार भी जिता कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है।

- विक्रमेर जैन, रामतरी

टेंड

दलितों को बांटने का षड्यंत्र

हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा उच्चतम अदालत के आदेश के कार्यक्रम को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का पैंतरा दलितों को फिर से बांटने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी निर्णय है।

-मायावती, पूर्व सीएम

सो रही कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से कांग्रेस सरकार सो रही है। अवैध अतिक्रमण, महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस सरकार कार्रवाई की बजाय अपने आलाकमान का मुँह देखती है।

-अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

बार-बार परीक्षाएं स्थगित

यूपी पीसीएस की प्रिलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई। यूपी टेक्निकल एजुकेशन कर्मचारी-2021 की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया। बार-बार परीक्षाएं स्थगित करना, पेपरलीक और भ्रष्टाचार के जरिये युवाओं का भविष्य बर्बाद करना भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है।

-प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेत्री

ओम पुरी को नमन

ओम पुरी को परिश्रम की त्वचा के नीचे जल्दी से पुताना एक उपहार था जो सायद भगवान ने उसे दिया था, अन्यथा कोई उसके द्वारा निभाई गई असंख्य भूमिकाओं के साथ कैसे न्याय कर सकता है। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि!

- राज बब्बर, अभिनेता

करंट अफेयर

सऊदी अरब की महिलाओं में योग है लोकप्रिय

रियाद। सऊदी अरब के लोगों ने सात साल पहले बिना किसी संकोच के योग को अपना लिया था और अब यह प्राचीन भारतीय विधा इस देश में काफी लोकप्रिय है तथा इसमें महिलाओं का प्रभुत्व है। देश की पहली प्रमाणित योग प्रशिक्षक और पद्म श्री सम्मान से नवाजी गई अरब की पहली नागरिक नोऊ मरवाई ने यह बात कही। मरवाई ने कहा कि सऊदी अरब के लोग स्वास्थ्य के लिए अच्छी किसी भी चीज को पसंद करते हैं। उन्होंने 2017 में सऊदी अरब में योग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह अब 2021 में स्थापित सऊदी योग समिति की प्रमुख तथा अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। मरवाई का कहना है कि सऊदी अरब में आज योग में महिलाओं का प्रभुत्व है। उन्होंने कहा कि अल वहला क्लब और सऊदी योग समिति द्वारा मक्का में आयोजित दूसरी सऊदी ओपन योग आसन चैंपियनशिप में 56 लड़कियों और 10 लड़कों ने भाग लिया। मरवाई जब 17 साल की थीं, तभी उन्हें ऑटोइम्यून रोग 'ल्यूपस परिवेमाटोसस' होने का पता चला था। उन्होंने योग के प्रति अपने रुझान को याद करते हुए कहा, चिकित्सकों ने मेरे माता-पिता से कहा कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे स्कूल न जाने के लिए कहा गया और तभी मैंने रियाद में घर पर ही योग सीखा।

ऑफ बीट

क्या आईयूडी के इस्तेमाल से स्तन कैंसर होता है?

एक नये अध्ययन में हार्मोन युक्त अंतर्गर्भाशयी उपकरण (आईयूडी) के इस्तेमाल और स्तन कैंसर के जोखिम के बीच संबंध पाए गए हैं। हार्मोन युक्त आईयूडी 'टी' के आकार का एक उपकरण होता है, जो गर्भाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कर अनचाहा गर्भ ठहरने से रोकता है। अध्ययन के नतीजे अहम हैं, लेकिन मीडिया में आई खबरों में आईयूडी के इस्तेमाल से स्तन कैंसर के खतरे में भारी वृद्धि के दावे अनावश्यक चिंता पैदा कर सकते हैं। आइए, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए आईयूडी का सहारा लेने वाली महिलाओं के लिए अध्ययन के निष्कर्ष के वास्तविक मायनों के बारे में बात करें। आईयूडी क्या होता है - आईयूडी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले गर्भनिरोधक उपकरण हैं। इन्हें गर्भाशय में प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे अनचाहे गर्भ को रोकने में मदद मिलती है। पुराने आईयूडी में गर्भनिरोधक घटक के रूप में तांबा मौजूद होता था, जो शुक्राणुओं को अंडाणु के निषेचन से रोकता था। जबकि, नये हार्मोन युक्त आईयूडी गर्भाशय में लेवोनोजेस्ट्रल नामक कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं। लेवोनोजेस्ट्रल शरीर में मौजूद प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करता है। तांबा और हार्मोन युक्त आईयूडी अनचाहा गर्भ रोकने में कई वर्षों से प्रभावी साबित हो रहे हैं।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
रिंग रोड नं. 2, गौरवपथ, बिलासपुर
फोन: 4010501271016,फैक्स-2710 18
ई-मेल: haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट: www.haribhoomi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 210

एक नई शुरुआत

भारत की विदेश नीति का यह पहलू पर्यवेक्षकों को चकित कर सकता है कि वह लगभग हर बहुपक्षीय समूह में शामिल होने के लिए कैसे तैयार रहता है। शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ही लेते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारत द्वारा एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों से अलग है जिनमें क्वाड भी शामिल है। परंतु गत सप्ताह ऐसे समूहों का महत्त्व सामने आया। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक पिछले कुछ समय में संभव नहीं हो पा रही थी लेकिन एससीओ शिखर बैठक के इस्लामाबाद में आयोजित होने के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह अवसर मिला कि वह सीमा पार जाएं और दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में नई जान फूंकें।

यह आठ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के निकाह के अवसर पर अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से दो बार बात की। वह सीमा पार गतिविधियों के बारे में कड़ा संदेश देने में कामयाब रहे और इस विषय पर भारत की लंबे समय से चली आ रही चिंता से अवगत कराया। उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के आपसी रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में रास्ते तलाश करने की दिशा में भी प्रयास किया। दोनों पक्षों की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास नहीं किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले महीनों में एक परिपक्व रास्ता तलाश किया जा सकेगा।

हाल के वर्षों में पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख यह रहा है कि वह उसे यथासंभव अलग-थलग कर दे। पाकिस्तान की आंतरिक उथल-पुथल ने भी इसमें योगदान किया है और इस तथ्य ने भी कि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। पहले तर्क दिए जाते थे कि सीमा पार व्यापार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करता है और उनके रिश्तों में स्थिरता लाता है। अब भारत में इस तर्क पर बहुत अधिक यकीन नहीं किया जा सकता है। इस लिहाज से अब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना की गुंजाइश है और ऐसा किया जाना चाहिए। शरीफ के पास अभी भी पाकिस्तान में काफी राजनीतिक शक्ति है क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री उनके भाई हैं। पद पर रहते हुए शरीफ ने कई बार इस संभावना के बारे में बात की। भारत की बात करें तो उसने 2019 में कश्मीर का दर्जा बदलने के बारे में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया होगा जो कूटनीतिक दायरे में ही रही थी।

इससे दो संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं: पहला, पाकिस्तान में अब यह क्षमता नहीं है कि वह भारत के काम को बाधित कर सके, चाहे वह कश्मीर से जुड़ा मुद्दा ही क्यों नहीं हो। दूसरा यह कि यह इस बात का संकेत है कि वहां का प्रतिष्ठान रिश्तों को सामान्य बनाने के नाम पर ऐसे कदमों की अनदेखी करने का इच्छुक है। चाहे जो भी हो सामान्यीकरण का ऐसा सवाल है जिसे अब खंगालने की जरूरत है। ऐसा भारत की चिंताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को भी उन्हें दूर करना चाहिए। इससे होने वाले लाभ शायद उतने व्यापक नहीं हों जितना कि उन्हें दो दशक पहले माना जाता था जब शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर घोषणापत्र के जरिये रिश्तों को नए सिरे से सुधारने की कोशिश की थी। परंतु इस बीच दोनों देशों के बीच तुलनात्मक असंतुलन भी बढ़ा है। दक्षिण एशिया में स्थिरता की एक नई राह नजर आ रही है।

बिनय सिन्हा

सऊदी अरब की महत्त्वाकांक्षा भरी तकनीकी छलांग

सऊदी अरब उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी वृद्धि को गति प्रदान कर रहा है और साइबरस्पेस पर नियंत्रण वाले देशों में अग्रणी बन रहा है। बता रहे हैं श्याम सरन

वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं में अग्रणी देशों की बात करें तो आम तौर पर सऊदी अरब का ध्यान नहीं आता। उसकी छवि अब भी अर्द्ध सामंती, रूढ़िवादी समाज की ही बनी हुई है, जहां वंशवादी राजशाही का शासन है। लेकिन हकीकत काफी अलग है। वली अहद यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले साल साल में वहां अभूतपूर्व आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुआ है, जिसने 3.4 करोड़ आबादी वाले देश को आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और उच्च आय वाले देशों में ला खड़ा किया है।

यह खाड़ी क्षेत्र में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे साक्षर देशों में से एक है। इसकी 98 फीसदी आबादी साक्षर है और 96 फीसदी महिलाएं भी साक्षर हैं। देश की 90 फीसदी से अधिक आबादी शहरों में रहती है और कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी 36 फीसदी है, जो भारत से भी अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की है और प्रति व्यक्ति आय 21,000 डॉलर है।

यह सही है कि सऊदी अरब की समृद्धि में तेल भंडारों और तेल उत्पादन का बड़ा योगदान है लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 के लिए एक विजन पर काम शुरू किया है, जिसमें तेल को छोड़कर बाकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। साथ ही आधुनिक विनिर्माण, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन तथा वित्तीय सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी यानी सॉवरिन वेल्थ फंड सऊदी अरब में ही है, जो 900 अरब डॉलर से अधिक की संपत्तियां संभालता है। इस भारी भरकम पूंजी से न केवल विजन 2030 के तहत महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को धन मिल रहा है बल्कि भारत समेत दूसरे देशों की परिसंपत्तियों में निवेश भी किया जा रहा है। तेल को निकाल दें तो बाकी सऊदी अर्थव्यवस्था इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी हासिल कर चुकी है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सऊदी अरब ने आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए उन्नत विज्ञान तथा तकनीक के विकास और इस्तेमाल पर भरपूर जोर दिया है। उसने मानव संसाधन में जमकर निवेश किया और उच्च कौशल वाली तथा तकनीक में माहिर श्रम बल तैयार किया, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी-खासी तादाद है। कुछ ही साल के भीतर यह इंटरनैशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। इसकी नैशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी का दुनिया भर में अच्छा रुतबा है। इसकी राजधानी रियाद में हर साल ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी फोरम (जीसीएफ) और ग्लोबल आर्टिफिशल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन होता है।

इस साल 2 और 3 अक्टूबर को मैंने चौथे जीसीएफ में हिस्सा लिया। मैं इसमें तीसरी बार गया था। मैं इससे पहले दो बार वहां हुए अनुभवों के बारे में इस समाचार पत्र में लिख चुका हूं। पिछले दो साल में मैंने खुद देखा है कि सऊदी अरब ने उन्नत तकनीकों के विकास और इस्तेमाल में कितनी उल्लेखनीय प्रगति की है।

इस वर्ष के जीसीएफ का विषय था 'एडवांसिंग कलेक्टिव एक्शन इन साइबर स्पेस।' फोरम इस बात पर सहमत था कि पूरी दुनिया के लिए एक ही साइबरस्पेस है, जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सीमाओं से परे है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा, जो आज के ध्रुवीकृत भूराजनीतिक माहौल में थोड़ा मुश्किल है। गाजा में साल भर से चल रही जंग के कारण सऊदी अरब में भी तनाव का माहौल है क्योंकि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र पर जंग की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति इस बात से और भी जटिल हो जाती है कि साइबर क्षमताओं और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का विकास तथा प्रयोग मुट्ठी भर ताकतवर बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियां ही कर रही हैं।

कंपनियां अक्सर होड़ और मुनाफे के लिए काम करती हैं। ऐसे में उन पर सरकारों के कायदे लागू करना हमेशा दिक्कत भरा होता है। साइबर तकनीक और एआई अभूतपूर्व तेजी से विकसित हो रही हैं। सरकारें उनके इस्तेमाल के कायदे तय करने की जुगत में ही लगी रहती हैं। इस क्षेत्र की कंपनियां नियमन के प्रयासों से यह कहकर बचती रहती हैं कि ऐसी कोशिशों को नवाचार में रुकावट नहीं बनना चाहिए। एआई के चैटजीपीटी जैसे उत्पादों को बाजार में उतारने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि उनका दुरुपयोग न हो। अमेरिकी नैशनल साइबर सिक्योरिटी के निदेशक रह चुके क्रिस इंग्लिस ने फोरम में अपनी बात रखते समय इस पर बहुत जोर दिया।

इंग्लिस ने यह भी कहा कि साइबरस्पेस नाजुक है और साइबर तकनीक तथा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के तेज विकास के चक्कर में इसकी मजबूती और सुरक्षा की अनदेखी की गई है। यही वजह है कि साइबर और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस दोनों में ही 'हमलावर' बचाने वालों पर हावी हैं और भारी पड़ रहे हैं।

मैं सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अब्दुल अल जुबैर और विश्व व्यापार संगठन के पूर्व महानिदेशक पास्कल लैमी के साथ साइबर कूटनीति के पैनल में शामिल था। उसमें स्वीकार किया गया कि ऐसे बहुपक्षीय रुख को आगे बढ़ाना मुश्किल है, जो खास तौर पर विकासशील देशों में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। मगर इस बात पर सहमति थी कि भूराजनीतिक खेमेबाजी के बाद भी साइबरस्पेस में बच्चों की सुरक्षा करने तथा स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग संभव है।

नवाचार और नियमन के बीच उचित संतुलन कायम रखने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी के सवाल पर मैंने तर्क दिया कि कंपनियां हमेशा नियम-कायदों और सरकारी नियंत्रण का विरोध करेंगी। सरकार को नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए लेकिन उसके लक्ष्य निजी कंपनी के मुताबिक नहीं हो सकते क्योंकि कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं। वे हमेशा होड़ में आगे रहने की कोशिश करती हैं। मैंने कहा कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी जरूरी हो तो भी इसकी डोर सरकार के हाथ में ही रहनी चाहिए।

फोरम में कुछ खास बातें सामने आईं। मसलन साइबर क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की रफ्तार उस पर ठीक से सोच-विचार करने तथा आपराधिक कृत्यों समेत उसके व्यापक दुरुपयोग को रोकने की देशों और सरकारों की क्षमता खत्म कर रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और कंपनियों के रवैये में होड़ का तत्त्व सामूहिक भावना को पनपने ही नहीं देता। तेज वृद्धि की संभावना तो बहुत बड़ी है मगर उसके साथ ही मौजूद खतरा असल में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है।

साइबरस्पेस और एआई ने ऐसी दुनिया बना दी है, जहां सर्वाधिक परिष्कृत तकनीकें भी तेजी से फैल जाती हैं। कई गरीब देशों के पास इस क्षेत्र में उन्नत क्षमताएं पहले ही आ चुकी हैं। अतीत के उलट अब उनके पास इतनी क्षमता है कि वे सशक्त बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ मिलकर साइबरस्पेस के वैश्विक संचालन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की अगुआई कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इकलौता मंच है, जिसके ऐसे प्रयासों को सभी स्वीकार करते हैं। किंतु इसका नेतृत्व तो भारत और सऊदी अरब जैसे देशों को ही करना होगा।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

क्वांटम तकनीक पर तेजी से बढ़ने की जरूरत

इस वर्ष 13 अगस्त का दिन क्वांटम तकनीक (टेक्नोलॉजी) के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय मानक एवं तकनीक संस्थान (एनआईएसटी) ने पहले तीन पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) मानकों की घोषणा की। पीक्यूसी वह तकनीक है, जिसमें अल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है और अहम जानकारी (डेटा) को अनधिकृत इस्तेमाल से बचाया जाता है।

इन मानकों की घोषणा के बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठानों में इस तकनीक के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब यह चिंता काफी हद तक दूर हो सकती है कि क्वांटम कंप्यूटरों के जरिये मौजूदा सुरक्षा उपायों (इन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल) को तोड़ न दिया जाए और पूरा साइबर तंत्र खतरे में न पड़ जाए।

आज हम जिस डिजिटल दुनिया को देख रहे हैं, उसमें क्वांटम तकनीक भारी उथल-पुथल लाने वाली है। डिजिटल नवाचार के जरिये पिछले पांच दशकों में तेज बदलाव देखने के बाद अब हम क्वांटम तकनीक की मदद से और भी तेज बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। बड़े बदलाव लाने की क्षमता वाली क्वांटम तकनीक उद्योग, अर्थतंत्र और सुरक्षा को अभूतपूर्व तेजी के साथ नई शक्ल देगी। इसलिए यह वैश्विक तकनीकी होड़ का केंद्र बन गई है और दुनिया के प्रमुख देश क्रांति लाने वाले इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं।

इस समय दो प्रमुख तकनीकी रुझान हैं, पीक्यूसी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (क्यूकेडी)। पीक्यूसी में क्रिप्टोग्राफ वाले अल्गोरिदम तैयार किए जाते हैं, जिन पर क्वांटम हमलों का असर ही नहीं होता। मगर क्यूकेडी सुरक्षा उपाय पुख्ता करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करती है। इस बात पर एक राय नहीं है कि आगे जाकर दोनों में किसका वर्चस्व होगा। दुनिया दो खेमों में बंट गई है: अमेरिका पीक्यूसी का हिमायती है मगर चीन और रूस क्यूकेडी पर दांव लगा रहे हैं।

नवंबर 2023 में अमेरिका ने पहल करते हुए अपनी सभी संघीय एजेंसियों को सुरक्षा के लिए पीक्यूसी के इस्तेमाल का निर्देश दिया, जिसके बाद पीक्यूसी मानकों के विकास में तेजी आ गई। एनआईएसटी 2016 से इन मानकों पर काम कर रहा था और कुछ ही महीनों में उसने इन्हें तैयार कर दिया। इस बीच रूस और चीन क्यूकेडी में आगे निकल रहे हैं। चीन ने 2017 में पेइचिंग और शांघाई के बीच 2,000 किलोमीटर लंबा क्यूकेडी-सिक्योर्ड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार कर लिया जिसमें एक हॉप लगभग 100 किलोमीटर का था। हॉप संदेश (डेटा) भेजने वाले और इसे प्राप्त करने वाले पक्षों के बीच नेटवर्क पथ का एक हिस्सा होता है। भारत ने 2019 में 130 किलोमीटर का सिंगल-हॉप क्यूकेडी तैयार कर लिया। मगर जनवरी 2024 में चीन और रूस ने उपग्रह से जोड़कर क्यूकेडी तैयार किया, जिसने एक दूसरे से लगभग 3,800 किलोमीटर दूर स्थित मॉस्को और उरुमकी को जोड़ दिया।

अजय कुमार

भारत क्वांटम तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इकाइयां ऐसी तकनीक ला रही हैं, जो अमेरिकी और चीनी तकनीक को भी चुनौती देती है। भारतीय स्टार्टअप इकाइयों ने एनआईएसटी के अनुकूल पीक्यूसी तकनीक तैयार की हैं और 200 किलोमीटर सिंगल-हॉप सिस्टम सहित फाइबर के जरिये क्यूकेडी भी तैयार कर लिया है। अप्रैल 2003 में सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये बजट वाले राष्ट्रीय क्वांटम अभियान को मंजूरी दी। इस अभियान का लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और सामग्री से जुड़ा था। मगर इतनी प्रगति के बावजूद इन तकनीकों के व्यापक इस्तेमाल के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है।

इसके लिए बजट के साथ ठोस नीतिगत ढांचा भी चाहिए। इस ढांचे के मुख्य बिंदुओं में एक दूसरे के साथ कामकाज सुगम बनाना और गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए अनिवार्य मानकों की स्थापना तथा बाजार में इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीदारी भी शामिल हैं। ये उपाय निजी क्षेत्र की दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मजबूत तथा नवाचार पर चलने वाला तंत्र तैयार करने में मददगार हो सकते हैं।

उभरती तकनीकों की प्रगति देखने, संसाधन आबंटित करने और उन पर लगातार नजर रखने के लिए क्रियान्वयन की स्पष्ट रणनीति तैयार करने में भी सरकार की अहम भूमिका है। इससे शुरुआती नीतिगत उपाय अच्छी तरह लागू करने और निर्बाध एवं भविष्य की तरफ सटीक एवं स्थायी कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार का इस क्षेत्र में प्रदर्शन सराहनीय रहा है। देश में 'आधार' की शुरुआत 2009-10 में हो गई थी मगर इसका व्यापक इस्तेमाल और इसके जरिये पहचान का तत्काल सत्यापन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के समय ही हो पाया। इसी तरह यूपीआई को सफल एवं लोकप्रिय बनाने एवं इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया और डिजिटल तकनीक से अनभिज्ञ लोगों को प्रशिक्षित किया।

किंतु अंतरिक्ष क्षेत्र में उलटा उदाहरण दिखता है। इसे निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप इकाइयों के लिए खोलने का सरकार का 2020 का फैसला बहुत बड़ा सुधार था मगर शुरुआत में नाकाम रहा। इसमें तेजी अक्टूबर 2022 में आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक रक्षा प्रदर्शनी में अंतरिक्ष से संबंधित 75 रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडिक्स) अभियान शुरू किए। मजबूत आईडिक्स ढांचे से अंतरिक्ष स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा मिला है और इससे सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद मिलती है। इससे पता चलता है कि बड़े सरकारी सुधारों के साथ क्रियान्वयन रणनीति भी चलनी चाहिए।

पीक्यूसी और क्यूकेडी अहम हैं और दोनों को बढ़ावा देने के लिए जांच नियमावली एवं गुणवत्ता मानक तैयार करने चाहिए। सरकार को इनकी खरीद में तेजी लानी चाहिए ताकि महत्त्वपूर्ण डिजिटल ढांचे की क्वांटम से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मिसाल के लिए वह 2026 की समयसीमा तय कर सकती है। हमारा स्टार्टअप तंत्र खासा मजबूत है, इसलिए भारत इनका इस्तेमाल जल्दी शुरू कर सकता है। आईडेक्स के अंतर्गत एक स्टार्टअप इकाई के 200 किलोमीटर सिंगल-हॉप क्यूकेडी सॉल्यूशन को प्रमाणन हासिल करने में दो साल से ज्यादा लग गए। तेजी से दौड़ती दुनिया में इतना समय लगना समझ से परे है। होड़ में बने रहने के लिए हमें तकनीक को तुरंत अपनाना होगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शोध एवं विकास में अग्रणी है लेकिन क्वांटम तकनीक के व्यापक क्रियान्वयन के लिए आरऐंडी से बड़े दायरे वाली व्यवस्था चाहिए। क्वांटम तकनीक को हमेशा अनुसंधान का हिस्सा माना जाता रहा मगर इस समय वह मंत्रालय के प्रमुख प्रदर्शन मानकों के दायरे से बाहर है। यह अंतर पाटने के लिए सरकार इस तकनीक के इस्तेमाल की गति तेज करने तथा इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपने की सोच सकती है। इससे देश भर में इसका इस्तेमाल अधिक तालमेल के साथ हो पाएगा।

भारत को अपनी स्टार्टअप इकाइयों की शुरुआती सफलता का फायदा उठाते हुए क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने के लिए देर किए बगैर अधिक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिए। सरकार ने अब तक क्वांटम शोध के इस्तेमाल एवं क्रियान्वयन में सराहनीय मदद की है मगर इसे अपनाने एवं इसके क्रियान्वयन का स्पष्ट ढांचा नहीं होने पर देश वैश्विक होड़ में पीछे छूट सकता है।

(लेखक रक्षा सचिव रह चुके हैं एवं आईआईटी कानपुर में अतिथि प्राध्यापक हैं)

आपका पक्ष

प्रदूषण रोकने के लिए एकजुटता की जरूरत

भारत की छवि पूरी दुनिया में प्रकृति प्रधान और कृषि से प्रसिद्ध है जिसे हम प्रदूषण बढ़ाकर खराब कर रहे हैं। हम प्रदूषण से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। अगर हमने पर्यावरण की देखभाल के लिए अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई तो बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल भी सर्दी की दस्तक से पहले ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है। देश में भी जिस तेजी से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए कड़े नियम लागू करने की जरूरत है। प्रदूषण के कारण जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसका इलाज हमें खुद ही करना होगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के बढ़ने पर वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए सम-विषम नियम लाती है तो लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। लोग शायद अपनी सहूलियत के लिए इस नियम का विरोध करते हैं और प्रदूषण की समस्या पर विचार नहीं करते हैं। देश में जिस तेजी से प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है उसके लिए हर दिन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। मगर जब सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने लगता है तो ही इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए जाने लगते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए हर छोटे-बड़े आम लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। सरकार को भी प्रदूषण रोकथाम के लिए कड़े नियम लाने के साथ-साथ इसे कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सभी दलों को भी मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस समस्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में देश के उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण पराली जलाना भी रहा है। इससे निपटने के लिए कुछ विशेषज्ञ तथा अन्य लोग यह सलाह देते हैं कि किसानों को धान की जगह अन्य फसलें उगानी चाहिए। लेकिन वे भूल जाते हैं कि कुछ किसान तो गेहूं के अवशेष को भी जलाकर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। इसलिए क्या गेहूं की खेती करना भी बंद कर देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पंजाब में अमृतसर के बाहरी इलाके में शुक्रवार को खेतों में पड़ी पराली जलाता एक किसान

एनबीएफसी पर आरबीआई की कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चार एनबीएफसी कंपनियों के प्रति जो कदम उठाया है यह एक सकारात्मक शुरुआत है लेकिन एनबीएफसी उद्योग में सुधार के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार और नियामकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके और एनबीएफसी उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। आरबीआई की चार एनबीएफसी कंपनियों पर की गई कार्रवाई यह दर्शाती है कि आरबीआई की कड़ी नजर एनबीएफसी उद्योग पर है और उचित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। उपभोक्ताओं को भी इस मामले में सतर्क रहने और ऋण लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में पहले चरण में शुक्रवार को 11 टन चिकित्सा सामग्री भेजी। वह कुल 33 टन चिकित्सा सामग्री भेजेगा।

कल्पमेधा

शिक्षा का अर्थ है वह जानना, जो आपको पता भी नहीं था कि वह आपको पता नहीं था।

- डेनियल जे. बूर्स्टिन

नागरिकता का सवाल

बांग्लादेश से आकर असम में पनाह पाए या फिर अवैध रूप से रह रहे लोगों की नागरिकता का सवाल लंबे समय से उलझा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों की नागरिकता तय करने के मकसद से संविधान में जोड़ी गई धारा 6ए पूरी तरह जायज है। दरअसल, केंद्र सरकार का कहना था कि यह धारा नागरिकता और भाषा-संस्कृति संबंधी संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करती है। बांग्लादेश से आकर बसे लोगों की वजह से असम में जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ा है, वहां की भाषा और संस्कृति भी प्रभावित हुई है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसे लोगों की वजह से वहां की भाषा और संस्कृति पर बुरा असर पड़ा है। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यानी अब 1 जनवरी, 1966 से पहले आए लोगों को स्वतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और उसके बाद 24 मार्च, 1971 के बीच आए लोगों को नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आए लोगों को अवैध माना जाएगा और सरकार उन्हें वापस भेजने का प्रबंध करेगी।

दरअसल, केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार करना चाहती है। उसमें असम सरकार लगातार बांग्लादेश से आई मुसलिम आबादी का सवाल उठाती रही है। उसका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य के कई जिलों में उनकी आबादी बहुसंख्यक हो गई है। मगर उनकी पहचान करने में उसे कठिनाई पेश आती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि राज्य सरकार ऐसे नागरिकों की पहचान कर बताए कि कितने विदेशी नागरिक वहां रह रहे हैं और कितनों को वापस भेजा गया है। मगर सरकार उसका आंकड़ा पेश करने में विफल रही। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला पुराना है, इसे लेकर वहां करीब छह वर्ष तक आंदोलन चला था। उसे शांत करने के मकसद से तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1985 में बांग्लादेश सरकार और असम छात्र संगठन से बातचीत कर 6ए का प्रावधान किया था। बांग्लादेश सरकार अब भी भारत में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। मगर यह तभी संभव है, जब असम सरकार पारदर्शी तरीके से उनकी पहचान करे। देखना है, यह काम वह कैसे और कब तक कर पाती है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का मुद्दा इसलिए विवादास्पद हो गया था कि ठीक से पहचान किए बिना उन्हें पृथकता केंद्रों में भेजा जाने लगा। उनमें से कई ऐसे नागरिक भी बताए जाते हैं, जो भारतीय नागरिकता कानून के दायरे में आते हैं, मगर उनके पास पहचान के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे नागरिकों को बांग्लादेश भेजने से उनके सामने नई दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। वहां जाकर उन्हें नागरिकता न मिली तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे। किसी संकट के समय मानवीय आधार पर दूसरे देश के नागरिकों को पनाह देना हर देश का धर्म है, पर किसी लोभ में अवैध तरीके से आकर लोग रहने लगें, तो उससे न केवल देश की बुनियादी सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी पेश आने लगती हैं। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में रहने देने के पक्ष में शायद ही कोई हो, पर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें वापस भेजना भी उचित नहीं कहा जा सकता।

विवाह की उम्र

बाल विवाह से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, वह वक्त का तकाजा है और इससे संबंधित कानून को लागू करने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाला भी। देश भर में विभिन्न समुदायों के बीच परंपरा या व्यक्तिगत कानूनों की वजह से आज भी बाल विवाह करा दिए जाते हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिन बच्चों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है, वे इस मामले में कितनी परिपक्व समझ रखते हैं। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अहम है। अदालत ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि इस कानून में कुछ खामियां हैं और इसे सफल बनाने के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय के पक्ष का ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है कि बाल विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है।

दरअसल, समाज में अब भी कुछ ऐसी रिवायतें जारी हैं, जो न केवल किसी समाज में प्रतिगामी मूल्यों की वाहक हैं, बल्कि उनके जरिए कई बार मानवाधिकारों का भी हनन होता है। बाल विवाह ऐसी ही एक परंपरा है, जो कानून की कसौटी पर तो अनुचित है, मगर व्यवहार में बदस्तूर कायम है। बच्चों का विवाह कराते हुए इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि कम आयु के बच्चे अपने विवाह को लेकर कोई परिपक्व फैसला नहीं कर सकते। अभिभावकों के फैसले का विरोध न कर पाने या असहमति न जता पाने की वजह से जो उन पर थोपा जाता है, उसे वे मजबूरन स्वीकार कर लेते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में बाल विवाह कराए जाते हैं और कानून वहां लाचार खड़ा दिखता है। जाहिर है, इस समस्या की परतें और जटिलताओं के मद्देनजर बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए वक्त के मुताबिक कानूनों में जरूरी बदलाव के साथ-साथ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और अलग-अलग समुदाय के हिसाब से रणनीति बनाने जरूरत है।

जलवायु संकट और दूर होते लक्ष्य

मौजूदा जलवायु संकट पर सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक नीतियों का है, विशेषकर तब जब पेरिस जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 और 2050 के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

कुशाग्र राजेंद्र

जलवायु संकट दिनोंदिन गहरा रहा है। हर वर्ष गर्मी कुछ बढ़ी हुई दर्ज होने लगी है। वैश्विक ताप और इससे जुड़े हर आंकड़े लगातार बढ़ते संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। जलवायु संकट से निपटने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो अब और बढ़ रहा है। वायुमंडल में पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों की मात्रा चरम पर है। ब्लूमबर्ग के आनलाइन आंकड़ों के मुताबिक अभी वायुमंडल में कार्बन डाइआक्साइड का ग्राफ 421.44 पीपीएम तक जा पहुंचा है, जो पृथ्वी के संतुलित तापमान के लिए जरूरी (350 पीपीएम) पैमाने से 71.44 ज्यादा है।

'मार्केटर रिसर्च', बर्लिन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। यही स्थिति रही, तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले चार साल और नौ महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में लगभग 23 साल का समय शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए, लंबे विचार-विमर्श और खींचतान के बाद, 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे। इसे अब तक का सबसे आशावादी समझौता माना गया था। इसके बावजूद वैश्विक तापमान में वृद्धि लगातार होती जा रही है। 'यूनाइटेड इन साइंस' की रपट तो और भी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान नीतियों के तहत, इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। यह जलवायु संकट से बचाव के लिए गंभीर चेतावनी है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि पेरिस समझौते से पहले के एक दशक में कोई प्रभावी काम नहीं हुआ। जब यह समझौता 2015 में लागू हुआ, उस समय अनुमान था कि 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा सोलह फीसद बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान किए गए वैश्विक प्रयासों का ही परिणाम है कि 2030 तक यह अनुमानित वृद्धि घट कर तीन फीसद तक आ गई है। फिर भी यह प्रयास अभी भी पर्याप्त नहीं है। पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार, पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लिए 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में क्रमशः 28 और 42 फीसद की कमी होनी चाहिए थी। मगर हम अब भी उत्सर्जन कम करने के बजाय उसमें कम से कम तीन फीसद की वृद्धि की राह पर हैं।

अगर जलवायु परिवर्तन के कारणों और इसके प्रभावों पर नजर डालें, तो हर स्तर पर न केवल एक असमान व्यवस्था जिम्मेदार दिखती है, बल्कि इसका प्रभाव भी वैश्विक स्तर पर अलग-अलग दिखाई देता है। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों या क्षेत्रों पर पड़ता है, जिनका इसमें योगदान बहुत कम या नगण्य होता है। यह समझ जलवायु विमर्श की शुरुआत से ही बननी शुरू हो गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में आयोजित स्टाकहोम सम्मेलन में पर्यावरणीय क्षरण को गरीबी के नजरिए से देखने की वकालत की थी।

मौजूदा जलवायु संकट और पर्यावरण क्षरण का स्वरूप व्यापक और वैश्विक है, लेकिन उससे निपटने की आर्थिक क्षमता प्रत्येक देश में असमान

विकास की वजह से अलग-अलग है। इस असमानता के कारण, पिछले पांच दशकों में कई समझौते किए गए और अनेक बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन ओजोन परत के छिद्र को छोड़ कर किसी भी क्षेत्र में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। इसके साथ-साथ, बढ़ते जलवायु संकट में पश्चिमी या विकसित

> **'मार्केटर रिसर्च', बर्लिन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। यही स्थिति रही, तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले चार साल और नौ महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में लगभग 23 वर्ष का समय शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए, लंबे विचार-विमर्श और खींचतान के बाद, 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे। इसे अब तक का सबसे आशावादी समझौता माना गया था।**

देशों का योगदान अधिक रहा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वैश्विक संदर्भ में ऐसा नहीं दिखता।

वैश्विक परिदृश्य में, पारदर्शिता बढ़ने के बावजूद, सभी देशों के बीच 'क्षमता के अनुसार साझा, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत पर केवल सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करने में विकसित देश किसी भी प्रकार की संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं, विकासशील देशों, जैसे भारत और ब्राजील, की प्राथमिकताएं अपनी विशाल जनसंख्या को बुनियादी संसाधन मुहैया कराने पर केंद्रित हैं। दूसरी ओर, गरीब देश, विशेषकर समुद्री किनारों पर बसे या द्वीपीय देश, मौजूदा वैश्विक आर्थिक तंत्र के शिकार बन रहे हैं और जलवायु संकट का सबसे अधिक दंश झेल रहे हैं।

मौजूदा जलवायु संकट पर सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक नीतियों का है, विशेषकर तब जब पेरिस जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 और 2050 के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसी भी आर्थिक गतिविधि पर लागू कर की दर या उसमें दी गई छूट इस बात का संकेत देती है कि जलवायु संकट से निपटने के हमारे प्रयास कितने प्रभावी हैं। इसका कारण यह है कि हर आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन से जुड़ी होती है। मसलन, आज भी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत है और इसके उत्पादन और उपयोग पर अभी भी सरकारी मदद दी जा रही है, जो स्पष्ट रूप से जलवायु संकट को बढ़ावा देने वाली नीति है। विकासशील देश इसी व्यवस्था पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास हरित ऊर्जा विकसित करने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही विकसित देशों से तकनीकी सहायता और आर्थिक साधन मिल रहे हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जलवायु संकट में मौजूदा वित्तीय व्यवस्था, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और अन्य संस्थाओं के दशकों से चले आ रहे आग्रह के बावजूद, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली परियोजनाओं को अनुदान दे रही है, जबकि स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए थी। देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र का दबाव समूह या 'कारपोरेट लाबी' भी शामिल है, ऐसी वित्तीय व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जो कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करती है।

वैश्विक दक्षिण के देशों में कारपोरेट का व्यवहार एक परजीवी के समान है, जो सार्वजनिक धन को विकास की आवश्यकताओं जैसे गरीबी और पिछड़ेपन की आड़ में अनुदान के रूप में जलवायु संकट से संबंधित परियोजनाओं में झोंक कर मुनाफा कमा रहा है। 'एक्शन ऐड' की मौजूदा रपट अधिकांश देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों में, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था पर कारपोरेट लाबी के प्रभावी पकड़ को जिम्मेदार बताती है। इसमें विकसित देशों द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के तहत 'जलवायु वित्त' के खोखले वादों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।

जलवायु संकट अब अपने विकराल रूप में आ चुका है। ऐसे में कारपोरेट को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और वैश्विक समुदाय को लाबी संस्कृति पर नियंत्रण लगाना होगा, ताकि सार्वजनिक वित्त का उपयोग जलवायु संकट को कम करने और इसके प्रभावों से बचाव के लिए आवश्यक क्षमता के विस्तार में किया जा सके। विकसित देशों को भी वैश्विक ताप में अपने योगदान और असमान विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका को स्वीकार कर 'क्षमता के अनुसार साझा, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत में बाधा डालने से बचना होगा।

मुखौटे वाली भीड़

विमल कुमार

अलग-अलग शहरों, कस्बों और गांवों में निर्मित हो रही एक तरह की भीड़ एक विचित्र सामूहिक नशे की शिकार लगती है। यह आयोजित भीड़ कई बार अश्लीलता की हद तक तेज बजते गानों पर उन्मादी शोर में डूबी दिखती है, जो रोटी-रोजगार के सवाल को भूल चुकी दिखती है। अलग-अलग 'ब्रांड' के रहनुमाओं के पीछे भाग रही यह भीड़ पुस्तकालय और विद्यालय से बेखबर दिखती है। नवनिर्मित और दिनोंदिन बढ़ती जा रही इस भीड़ की फसल को देख अलग-अलग रूप धरे धार्मिक और राजनीतिक व्यापारी प्रसन्न होते जा रहे हैं। कई बार कुछ रहनुमा जैसे लोग अलग-अलग वेश में भीड़ में उत्साह का संचार करते दिखते हैं। धार्मिक-राजनीतिक आकाओं के नए-नए फरमान इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बनने देना चाहते हैं। लोगों के होठ तो सुख ही रहे हैं, आंखों का पानी भी सूखता जा रहा है।

इंसान और इंसानियत से ज्यादा और भी कुछ महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसे शायद नहीं होना चाहिए था। ये सवाल गौण हैं कि कौन पहने देना चाहता है... क्यों पहने दिया जाए... इतनी हिम्मत बची है जो पढ़ोगे, आदि! किताब की दुकानें सिमटती जा रही हैं। महामारी के पहले लगभग सभी स्टेशनों पर किताब की समूह दुकानें थीं। वे आज बंद हो रही हैं या उन्हें समेट दिया गया है। किताब की जगहों पर चिप्स, कुरकुरे, चिस्किट पैर पसार चुके हैं। पुस्तकालयों को बर्बाद होते देखा जा सकता है। विद्यालयों में बच्चे किताबों का इंतजार कर रहे हैं। युवा पीढ़ी डीजे की ऊंची धुनों पर सिर्फ थिरक रही है। सरकारी नौकरी के लिए पागल, लेकिन निजीकरण का समर्थक मध्यवर्ग ऊंचे दाम देकर अपने बच्चों को दड़बेनुमा कमरों में रटने की मशीन बनाने पर आमादा है। वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों से ज्ञान प्राप्त करती आधुनिक संतानें बर्बाद होते संस्थानों के दौर में संदेश आगे भेजने और 'रील' बनाने की मशीन बनती जा रही हैं। पठनीयता में गिरावट से सबको लाभ है। बाजार के जाल को समझना आसान नहीं है। मतवादों से समर्थक में तब्दील हुई भीड़ में सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत ही कहां बची है!

हम दुर्भाग्य में धकेली हुई भीड़ हैं। इस बनाई हुई भीड़ को गुमराह करके दूसरे रास्तों पर हांक दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें अलग कहानी बयान करती हैं। यों भी तस्वीरें एक मुखौटा लगाए रहती हैं। बदहाल सरकारी अस्पताल भीड़ से भरे जा रहे हैं। प्रतिदिन दर्द से कराहते लोग थोड़ी-सी बची जिंदगी से लंबी लाइनों में लग जाते हैं। हाथ में पर्ची लिए एक कक्ष से दूसरे में भागते हुए लोग थक कर जिंदगी को कोसते हुए रिश्तों से भी कमजोर किसी दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। सुदूर अंचल से आए हुए लोग 'ओपीडी' की न बढ़ने वाली भीड़ में से गार्ड से बस एक बार डाक्टर साहब को दिखाने की मन्नत मांगते हैं। जांच कक्ष में जिंदगी के हैरतअंगेज कारनामों से मुखातिब कराती मशीनें जैसे अब तक किए गए कर्मों का हिसाब लिख रही होती हैं। अब तक निगले गए निवालों से अहम दवाइयों की लाइन में जेब को टटोलती कांपती कलाइयां जैसे जिंदगी के अवसान के आखिरी पल की गवाह बनती हैं।

इस भीड़ का हिस्सा बन जिंदगी को और जी लेने की जद्दोजहद में जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तभी हमें जिंदगी की नश्वरता की वास्तविक ध्वनि कानों में सुनाई पड़ती है। लगता है, देवताओं ने इंडानों की प्रार्थना कबूल करने से इनकार कर दिया है! गांव अपनी बेबसी के साथ हताशा के स्वर में जैसे बुदबुदा रहे हैं। टेलीविजन के अनुसार राय बनाता शहरी वर्ग मानो एकआयामी समझ और हताशा का शिकार होकर अब घुटन को विवश है। गांव और शहर के कुछ रास्ते ऐसे हैं कि इन रास्तों पर कोई नहीं आता, बस भूख आती है। भूख हर रोज आती है, क्योंकि भूख का कोई रविवार नहीं है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है कि भूख और सब्र उसके पेट का परीक्षण प्रतिदिन करते हैं।

हम स्वार्थ की भाषा और लाभ की आवाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर हम बाहर की यात्रा को भूलकर एक बार अंदर की यात्रा करें तो सत्य कितने खराब रूप में प्रकट होता है! हमारे सामाजिक, पारिवारिक सभी रिश्ते कितने खोखले होते जा रहे हैं! कितनी अर्थहीन संरचनाओं के बीच जीने के लिए विवश हैं हम लोग। एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया है। एक इंसान के रूप में इंसान का कोई महत्त्व नहीं है। हमारे छोटे-छोटे अहंकार और हित, किसी की आंखों के बड़े ख्वाबों को निर्दयतापूर्वक कुचल रहे हैं। मनुष्य होने का जो मूल है- आवेग, भावनाएं, रुदन, मुस्कुराहट, वही रौंद दी जा रही हैं। हम किसी न किसी प्रकार के नशे के आगोश में हैं। क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं।

स्वार्थ इतनी हावी है कि इंसान धीरे धीरे उपभोग की वस्तु बनता जा रहा है। हमें वस्तुओं का इस्तेमाल करना और रिश्तों को सहेजना चाहिए था, लेकिन हम रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं को सहेज रहे हैं। सच की आंच पर किसी भी रिश्ते को एक बार परख कर देखें, हल्की-सी तपिश पर पिघल कर अपने वास्तविक और विकृत स्वरूप में सामने आता है। सबके अपने तर्क, कसौटी और जीने के पैमाने हैं जो स्वाभाविक है, पर एक इंसान बनने की प्राथमिक पैमाने पर हम विफल हो रहे हैं। सजग होकर देखने पर सब कुछ कितना पारदर्शी तरीके से दिखता है। कितने खराब स्वरूप में चीजें क्रमिक रूप से विकसित और वैध होती जा रही हैं। एक इंसान के रूप में हमारे लिए यह सब स्वीकार कर पाना कठिन है, पर ठहर कर सोचने पर यह प्रश्न हमारा पीछा जरूर करता है कि क्या हम सचमुच इंसान बनने की प्रक्रिया में भी है?

दुनिया मेरे आगे

> **अगर हम बाहर की यात्रा को भूलकर एक बार अंदर की यात्रा करें तो सत्य कितने खराब रूप में प्रकट होता है! हमारे सामाजिक, पारिवारिक सभी रिश्ते कितने खोखले होते जा रहे हैं! कितनी अर्थहीन संरचनाओं के बीच जीने के लिए विवश हैं हम लोग। एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया है।**

अंतराल का चुनाव

झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। झारखंड में दो चरणों में और महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बीच केवल तीन दिन का अंतराल था, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में, तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव पांच अक्तूबर को हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव सात चरणों में हुआ था। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों प्रदेशों में विधानसभा चुनाव केवल 18 दिनों के अंतराल पर हुआ था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की चर्चा के बीच चुनाव आयोग प्रदेशों के विधानसभा चुनाव तीन दिन, ग्यारह दिन, पंद्रह दिन, दो चरण और पांच चरण में क्यों करवा रहा है? क्या चार प्रदेशों में एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकता था? एक देश एक चुनाव का मुद्दा हमारे देश में तब तूल पकड़ा, जब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने इसको प्रमुखता से उठाया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई। सवाल है कि जब सरकार इसके पक्ष में है और अन्य राज्यों में सरकार चला रही पार्टियों का समर्थन है, तो फिर चुनाव कुछ दिनों के अंतराल पर क्यों?

- अंकित कुमार, जम्मू

सबके लिए न्याय

बचपन से ही यह कौतूहल बना हुआ था कि न्याय की देवी की आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है? जिज्ञासावश कई बार बुद्धिजीवियों से इसका समाधान भी चाहा, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता रहा कि न्याय अंधा होता है। मगर एक ऐतिहासिक पहल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी है। इसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब न्याय की देवी के एक हाथ में दमन और शक्ति की प्रतीक तलवार की जगह अब एक पुस्तक आ गई है, जो कि संविधान है। इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से पारदर्शिता की ओर बढ़ेगी और आम जन-मानस में यह संदेश जाएगा कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं और कानून अब अंधा नहीं है। बंद आंखों से न्याय करने की अंग्रेजों की अब तक व्यवस्था को बदलते हुए खुली आंखों से सामनता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाली यह सराहनीय पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

- सान कुमार श्रीवास्तव, लखनऊ

संकट में वन्यजीव

'वन्यजीवों पर गहराता संकट' (लेख, 16 अक्तूबर) में विकास कार्यों से पर्यावरण संकट और जीवों के बीच बढ़ती असहजता पर ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही कुछ स्थायी विकल्प खोजने पर जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया वन्यजीवों के वास को सबसे पहले प्रभावित करती है। जंगलों में लगने वाली आग का असर वन्य जीवों के साथ-साथ पर्यावरण पर भी गंभीर असर डालता है। हालांकि भारत में केंद्र व राज्य की सरकारी एजंसियां मिल कर इस दिशा में कार्य कर रही हैं ताकि वन्य जीवों की अधिक से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लेकिन इसके लिए सभी संबंधित निकायों को मिल कर काम करना होगा। मगर इस दिशा में चल रहे प्रयासों में समन्वय का अभाव खास तौर से दिखता है। अक्सर लोग वन्य जीवों के इलाके में प्रवेश कर जाते हैं। जबकि कई जीव-जंतु जंगल सिमटने से शहरों की तरफ आने लगते हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं।

-दिव्यांशी, जौनपुर

सद्भाव की जरूरत

बराइच में पिछले दिनों एक युवक की मृत्यु और उसके बाद की स्थितियां दुखद हैं। शासन हर संभव प्रयासरत रहा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। मगर कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर मूर्ति विसर्जन या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के समय सामाजिक सद्भाव और सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह बिखर गया और हर्षोल्लास के माहौल को मातम में बदल दिया गया। ऐसी घटनाओं से शासन-प्रशासन और जनता को सीख लेनी होगी। कहां पर सावधानियां बरती जानी चाहिए, यह जानना भी बेहद जरूरी है। जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, उस समय पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस विभाग की अवावधानी और निगरानी की कमी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देती है। शासन और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जनता को भी आगे आना होगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शनिवार • 19 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जिस आदमी ने कभी किसी औरत को क्रोधित नहीं किया, वह अपने जीवन में असफल है

-क्रिस्टोफर मोर्ले

एक कदम आगे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत मिल रहे हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने उद्घाटन भाषण में न तो कश्मीर का जिक्र किया और ना ही भारत के विरुद्ध किसी तरह का तीखा बयान दिया। आम तौर पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर विवादित बयान देने से शहबाज पीछे नहीं हटते। अभी पिछले ही दोनों संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बहाल हो। लोगों को याद होगा कि एससीओ के विदेश

मंत्रियों की पिछले वर्ष गोवा में हुई बैठक भारत-पाक के बीच वाक युद्ध में बदल गई थी। वास्तव में एससीओ में पाकिस्तान को शामिल किए जाने के बाद भारत ज्यादा उत्साहित नहीं था। इन दोनों देशों की तकरार से एससीओ के पटरी से उतरने का खतरा था। इसे देखते हुए रूस और चीन ने सी प्लस 2 को आकार दिया था। मध्य एशिया के पांच देशों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ रूस और चीन इस मंच में शामिल हैं। इन देशों की यूरेशिया क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सामान चिंता है और रणनीतिक हितों में मेल है। एससीओ यदि यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा का कोई नया ढांचा खड़ा करने की पहल करता है तो यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय होगा। जहां तक भारत का सवाल है तो वह इस क्षेत्र को अपना विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र मानता है। हाल के दिनों में जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस भूभाग के साथ भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। जाहिर है एससीओ एक ऐसा मंच है जहां से भारत अपने रणनीति खेतों का संरक्षण कर सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि एससीओ की सक्रियता एवं जीवंतता बनी रहे। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल होते हैं तो एससीओ की प्रासंगिकता भी भारत के लिए बनी रहेगी। भारत का नजरिया साफ है। अगर पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद पर पुख्ता तौर पर लगाम लगाए तो नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के प्रति सकारात्मक रूख प्रदर्शित किया है और भारत ने भी उसका सम्मान किया है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस दिशा में कहां तक प्रगति होती है।

युद्ध नहीं, सिर्फ बुद्ध

भारत दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं दी हैं, दुनिया का समाधान बुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिये जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह कहा। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन को याद करते हुए कहा हमने दुनिया को बुद्ध की शिक्षाएं दी हैं। यह हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भाव ही दुनिया को बेहतर स्थान बनाने की कुंजी है। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद अवतरण की याद दिलाता है, जिसे मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का

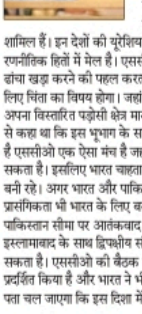

दर्जा दिए जाने को उन्होंने भगवान को बुद्ध को श्रद्धांजलि बताया। इस कार्यक्रम में चौदह देशों के शिक्षाविदों व भिक्षुओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने अलग साहित्यिक परंपराओं वाली भाषाओं, जो मौलिक हों और जिन्हें किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया है, उन्हें शास्त्रीय भाषा के तौर पर चिह्नित किया है। पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया व बंगाली को इसी माह शास्त्रीय भाषा के तौर पर चिह्नित किया है। इनमें से पाली भाषा को बुद्ध की विरासत माना जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं व प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में ही उपलब्ध हैं। यह भारत की प्राचीनतम ज्ञात भाषाओं में से है। जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। फिलवक्त रूस-यूक्रेन, इस्राइल-फिलिस्तीन जैसे मुल्कों के बीच जारी युद्ध में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वे विस्थापन झेलने को मजबूर हैं, उनको आवास, भोजन, पीने का पानी, जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से शांति का पथ-प्रशस्त करके अस्थिरता व अशांति से मुक्ति का मार्ग पाया जा सकता है। विश्व शांति के लिए बुद्ध को याद करना जख्म पर मलहम लगाने जैसा हो सकता है। इस सख्त वक्त में मोदी ने बुद्ध के ज्ञान को दोहरा कर बड़ा संदेश देने का सार्थक प्रयास किया है। हालांकि बौद्ध धर्म के दुनिया में जितने अनुयायी हैं, उस अनुपात में यदि उनकी शिक्षाओं पर तनिक भी आस्था होती तो इस अशांति से मानव यूं त्रस्त न होता।

कटाक्ष/ कबीरदास

अब पट्टी-मुक्त न्यायमूर्ति

ये लो कर लो बात। अब भाई लोगों ने न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटने का भी मोदी जी से कनेक्शन जोड़ दिया। कह रहे हैं कि जरूर मोदी जी की बात मानकर पट्टी हटायी गई है। मोदी जी ने ही कपड़ों से पहचानने की बात कही थी कि नहीं। न्याय की मूर्ति हूई तो क्या हुआ, कपड़ों से पहचानना है, तो देखना तो पड़ेगा। बस क्या था, न्याय की नयी मूर्ति की आंखों से पट्टी गायब और कपड़ों से पहचानना चालू! पट्टी मुक्ति की पट्टी मुक्ति और भारतीयता की भारतीयता।

हम तो कहेंगे कि जिनने अपनी आंखों पर विदेशीपन की पट्टी बांध रखी है, वे ही मूर्ति की आंखों से पट्टी के गायब होने का ग़ैर मचा रहे हैं। वर्ना न्याय के लिए आंख पर पट्टी बंधे होने की जरूरत तो किसी भी तरह से समझ में आने वाली नहीं है। उल्टे आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाए तो न्याय, न्याय नहीं, तुक्का हो जाता है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। पश्चिम वालों को न्याय करने के लिए, न्याय करने वाले का आंखें बंद करना क्यों जरूरी लगता है, ये पश्चिम वाले ही जानें। हम भारत वाले तो खुली आंखों से वल्कि आंखें फाड़कर न्याय करवाने में विश्वास करते हैं। हमारा न्याय, पश्चिम वालों से बारीक है, गहरा है। पश्चिम वाले करते होंगे सिर्फ सुनकर न्याय, हमारा न्याय देखकर होता है, देख-देखकर होता है। बिना देखे पता कैसे चलेगा कि न्याय मांगने वाला जनेऊधारी है या नहीं, शिखाधारी है या नहीं, तिलकधारी है या नहीं; अपरांधी भगवा गमछाधारी है या नहीं; हत्यारा धर्मध्वजाधारी है या नहीं? यह जाने बिना पूर्ण न्याय कैसे हो सकता है, जबकि हमारे यहां अलग-अलग किस्म के लोगों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है; संविधान में नहीं, मनुस्मृति में सही। आखिर, स्वदेशी तो मनुस्मृति ही है! और न्याय की मूर्ति की आंखों की पट्टी खुलने पर शोर मचाने वाले, बाकी बदलावों की बात क्यों नहीं करते हैं। मूर्ति को जो साड़ी मिल गई है, उसका क्या? और जो सिर पर मुकुट आ गया है, उसका क्या? और जो एक हाथ में तलवार की जगह, किताब आ गई है, उसका? क्या हुआ कि अभी संविधान की किताब है, है तो किताब ही; धीरे-धीरे मनुस्मृति भी आ जाएगी। मूर्ति, न्याय की देवी बन जाएगी और न्यायाधीश पुजारी। आगे-आगे देखिए होता है क्या-क्या?

मासूमों को ज्यादा नुकसान

ईरान-इस्राइल संघर्ष

डॉ. आमना मिर्जा

इतिहास में कुछ मुद्दे बेहद जटिल हैं। राष्ट्रीय हित, शक्ति के आयाम जटिलता को और बढ़ाते हैं। भू-राजनीति अतीत के मंथन में मिश्रित हो जाती है। तय करना आसान नहीं है कि कौन सही है क्योंकि आखिरकार, सत्य सापेक्ष होता है। इस संबंध में इस्राइल फिलिस्तीन गाजा महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। यह दुनिया के सबसे लंबे संघर्षों में से एक है। इस संकट में खास वर्ग ऐसा है, जिसकी आवाजें अक्सर अनसुनी हो जाती हैं। भू-राजनीतिक तनाव और सैन्य रुख हैं, दोनों पक्षों की महिलाएं स्वयं को पीड़ित पाती हैं। लिंग और जेंडर अलग-अलग हैं, लेकिन जीव विज्ञान में भेदभाव असमान वर्चस्व का कारण बन जाता है। दुखद वास्तविकता है कि शरीर युद्ध का मैदान बन जाते हैं। हम जानते हैं कि आत्मनिर्णय के लिए दशकों से चल रहे संघर्ष में गोलीबारी चल रही है। ये महिलाएं अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन करती हैं, उनका दृढ़ संकल्प एक प्रेरणा है।

हम सभी जानते हैं कि युद्धों के असमान प्रभाव होते हैं-महिलाओं, बच्चों, नवजात शिशुओं पर हिंसा का प्रभाव असंगत है। युद्ध क्षेत्रों में महिलाओं और परिवारों के लिए, यह न केवल परेशान करने वाली वास्तविकता है-उनके सबसे बुनियादी मानवाधिकारों और प्रजनन स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मातृ स्वास्थ्य के अलावा, महिलाओं का स्वास्थ्य भी मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की कमी से प्रभावित होता है। अफ़गानिस्तान गर्भावस्था, पोषण की कमी, मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का उपयोग करने वाली महिलाओं और लड़कियों में सहकर्ती संक्रमण अन्य मुद्दे हैं।

यौन उत्पीड़न सबसे प्राचीन युद्धोपराध

लैंगिक समानता को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन और अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन में प्रतिष्ठापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि युद्ध का सबसे प्राचीन, सबसे कम चर्चा वाला और शायद ही कभी निंदा किया जाने वाला अपराध यौन उत्पीड़न है। इस चर्चा में नारीवादी विदेश नीति को समझना महत्त्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य यौन और प्रजनन अधिकारों पर जोर देने के साथ लैंगिक समानता और महिलाओं के

अधिकारों को आगे बढ़ाना है। महिलाओं के अधिकारों को सरकारी नीति में एकीकृत करने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रित सहायता प्रदान करने के लिए रणनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण को अक्सर कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड, स्पेन जैसे देशों द्वारा समर्थन दिया गया है।

भारत अब वैश्विक परिवेश में अद्वितीय स्थान रखता है। देश ने साफ कहा है कि वह गाजा में जारी संघर्ष से बेहद परेशान है। यह आवाज भी उठाई है कि समय के साथ मानवीय संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है, इसका असर बाहर की चीज़ों पर भी पड़ रहा है। हालांकि वर्तमान संकट का एक महत्त्वपूर्ण कारण पिछले साल 7 अक्टूबर को इस्राइल में आतंकवादी हमले थे। इस संघर्ष का लंबा इतिहास है, हालांकि, वर्तमान संकट उस अकारण हमले से जुड़ा हुआ है। यह भी स्पष्ट निंदा का पात्र है। आतंकवाद और बंधक बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। बंधकों की रिहाई का संयुक्त राष्ट्र का फैसला ठीक है, और भारत ने शेष बंधकों की तत्काल बिना शर्त रिहाई का समर्थन किया है। आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का पालन करना सार्वभौमिक दायित्व है।

फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्लेनरी बैठक में भारत ने कहा कि द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध यथार्थवादी आख्यान का अनुसरण करते हैं। इसके राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। भारत ने किसी भी पहल के लिए कई कारकों को समक्ष रखा है। इस बार इस्राइल बनाम ईरान-हिजबुल्लाह संकट और इसका वैश्विक खासकर भारत के संदर्भ में संकट को लेकर केंद्रित है, युद्ध चरम पर है और महिला व बच्चों का विस्थापन भी बड़े स्तर पर हो रहा है, और होगा।

भारत सभी पक्षों से शांति के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह कर सकता है। इसने पार्टियों के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन किया है। हमेशा इस्राइल-फिलिस्तीन मुद्दे के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जिससे इस्राइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। हम अन्य वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों तरफ के नेता सुनने को तैयार नहीं, हर दिन 'इस रात की सुबह नहीं' जैसा है। बड़ी तस्वीर में गांधीवादी समाधान ही काम करेगा। किसी भी तरफ से निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है। हिंसा से अब तक कोई लाभ नहीं हो रहा है।

भारत सभी पक्षों से शांति के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह कर सकता है। इसने पार्टियों के बीच सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन किया है। हमेशा इस्राइल-फिलिस्तीन मुद्दे के लिए बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जिससे इस्राइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। हम अन्य वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों तरफ के नेता सुनने को तैयार नहीं, हर दिन 'इस रात की सुबह नहीं' जैसा है

दवाओं का बेअसर होना चिंतनीय

- बीमारियों के इलाज में दवाओं का कम होता असर वैश्विक संकट बन कर उभरा है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबाइल रेजिस्टेंस (एएमआर) को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और विकास के लिए बड़े चिंतनीय खतरों में से एक माना जा रहा है
- एंटीबायोटिक दवाओं के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से एएमआर पैदा होता है। ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करने लगते हैं, जो उनका प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं

(सौत : मीडिया इनपुट्स)

अगर शराब माफिया पर जोर नहीं चल पा रहा तो बेहतर है कि शराबबंदी खत्म कर दें नीतीश जी। कम से कम असली शराब पियेंगे तो मरेंगे नहीं लोग।

अशोक कुमार पाण्डेय, पत्रकार
@Ashok_Kashmir

वांगचुक अनशन

सुरेश भाई

हिमालय बचाने की जद्दोजहद

देश के जाने-माने पर्यावरणविद् व मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक हिमालय की आवाज को बुलंद करने के लिए लेह से 1000 किमी पैदल चलकर 3 सितम्बर को दिल्ली पहुंचे। मार्च 2024 में भी उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ लंबा उपवास किया था, लेकिन इस बार जब वे पैदल दिल्ली पहुंचे तो उनके 150 से अधिक पैदल यात्रियों को दिल्ली सिंघु बॉर्डर पर ही गिरफ्तार किया गया। बाद में 2 अक्टूबर को छोड़ भी दिया गया। इस व्यक्तार को देखकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वे लद्दाख भवन में ही अनशन पर बैठ गए। यहां भी 13 अक्टूबर को पुलिस ने प्रदर्शन के आरोप में उनके समर्थकों को हिरासत में लिया है।

सोनम वांगचुक महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को लेकर सीमांत क्षेत्र लद्दाख से हिमालय बचाने की आवाज दे रहे हैं। उनकी आवाज को सुनना जरूरी है। लद्दाख को लगभग 4 वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तभी से यहां लोग अपनी संस्कृति, पहचान, पर्यावरण बचाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की छठवीं अनुसूची के अनुसार वहां की 97 फीसद जनजातीय समाज को अधिकार मिले। इस विषय पर सितम्बर 2019 में छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई थी, जिसके लिए 6 मार्च 2024 से लद्दाख की राजधानी लेह में हजारों लोग खुले आसमान के नीचे बर्फीली ठंड में रात-दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वांगचुक ने अपने इस उपवास का नाम 'पर्यावरण उपवास' दिया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत छठी अनुसूची में प्रशासनिक विभागों में स्वतंत्र जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है। जिसमें राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है (जबकि छठी अनुसूची के मुताबिक जिला परिषद की अनुमति से ही क्षेत्र में उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि वांगचुक छठी अनुसूची के तहत राज्य को दर्जा दिलाना चाहते हैं और अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान कर

सकती है। अतः दूसरों के हस्तक्षेप के बिना वहां मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों के अनुसार यहां की भी व्यवस्था चल सकती है। यहां से मुखर आवाज निकल रही है कि अगर लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम में खनन और उद्योगों को अनुमति दी गई तो कुछ ही समय में ग्लेशियर सूख जाएंगे। इस संबंध में वांगचुक ने चेतावनी दी है कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों से यहां के पिघलते ग्लेशियरों का असर दो अरब लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। ताजा पानी का यह सबसे बड़ा भंडार है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहां पहुंचने वाली अंधाधुंध गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं सफेद चमचमाती बर्फ पर बैठ जाता है। यदि यह निरंतर जारी रहेगा है तो जलवायु शरणार्थी बन जाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते भी लद्दाख के लोगों ने मांग रखी थी कि लोक सभा के साथ राज्य सभा की एक सीट भी यहां के जनजातीय समाज के हित में मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि 1986 में वांगचुक के पिता ने भी अनशन किया था जो लद्दाख के आदिवासियों के अधिकारों के बारे में था। उस समय अनशन के 16वें दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से उड़ान भरकर जूस के गिलास के साथ वहां पहुंची थी और अनशन तुड़वाकर उनकी मांग को पूरा किया था। अभी उनकी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से है, जिसके लिए वे दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलकर वे प्रत्यक्ष रूप में यह मांग रखना चाहते हैं। सवाल तो है कि जब 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में अन्ना हजारे के अनशन के 13वें दिन बाद पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पास किया गया था तो लद्दाख की समस्याएं तो मौजूदा प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी के संज्ञान में है। और इसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इसलिए वे आस लगाए है कि उन्हें न्याय तो मिलना ही चाहिए।

काबिले गौर है कि सोनम वांगचुक देश का गौरव है। उन्होंने 2021 में इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटर टैंक बनवाए थे जिसमें लद्दाख में रहने वाले जवानों को एक आरामदायक जगह मिल सकी है। इसके साथ ही उन्होंने कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई है। ग्लेशियर के पास रहने वाले नौजवानों की जलापूर्ति के लिए उन्होंने तकनीकी ईजाद की है। आज वे लद्दाखा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने ही अनशन पर बैठे हुए हैं, जो पूरी तरह से बर्फ के संवेदनशील पर्यावरण को बचाने के साथ वहां के निवासियों के अधिकार के लिए संवैधानिक उपाय की मांग पर आधारित है। हर रोज दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित लद्दाख भवन के बाहर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से दर्जनों लोग मिलकर समर्थन दे रहे हैं। केंद्र सरकार को भी हिमालय पुत्र सोनम वांगचुक का सम्मान करना चाहिए। समय रहते यदि उनकी बात को नहीं सुना गया तो हिमालय के पर्यावरण के साथ न्याय नहीं होगा।

कृत्य ओशो

ध्यान

तुम्हारे जीवन की शैली होनी चाहिए। उसका एक हिस्सा नहीं। अन्यथा पाकर भी तुम उसे खो दोगे। यदि एक घंटे के लिए तुम निष्क्रिय हो तो तेईस घंटे के लिए तुम सक्रिय होओगे। सक्रिय शक्तियां अधिक होंगी और निष्क्रिय में जो तुम भी पाओगे वे उसे नष्ट कर देंगे। सक्रिय शक्तियां उसे नष्ट कर देंगी। और अगल दिन तुम फिर वही करोगे: तेईस घंटे तुम कर्ता को इकट्ठा करते रहोगे और एक घंटे के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। यह कठिन होगा। तो कार्य और कृत्य के प्रति तुम्हें दृष्टिकोण बदलना होगा। इसीलिए यह दूसरी विधि है। कार्य को खेल समझना चाहिए, कार्य नहीं। कार्य को लीला की तरह, एक खेल की तरह लेना चाहिए। इसके प्रति तुम्हें गंभीर नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही जैसे बच्चे खेलते हैं। यह निष्प्रयोजन है। कुछ भी पाना नहीं है। बस कृत्य का ही आनंद लेना है। यदि कभी-कभी तुम खेलो तो ओर तुम्हें स्पष्ट हो सकता है। जब तुम कार्य करते हो तो अलग बात होती है। तुम गंभीर होते हो। बोझ से दबे होते हो। उत्तरदायी होते हो। चिंतित होते हो। परेशान होते हो। क्योंकि परिणाम तुम्हारा लक्ष्य होता है। स्वयं कार्य मात्र ही आनंद नहीं देता, असली बात भविष्य में, परिणाम में होती है। खेल में कोई परिणाम नहीं होता। खेलना ही आनंदपूर्ण होता है। और तुम चिंतित नहीं होते। खेल कोई गंभीर बात नहीं है। यदि तुम गंभीर दिखाई भी पड़ते हो तो बस दिखावा होता है। खेल में तुम प्रक्रिया का ही आनंद लेते हो। कार्य में प्रक्रिया का आनंद नहीं लिया जाता। लक्ष्य, परिणाम महत्त्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया को किसी न किसी तरह झेलना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। क्योंकि परिणाम पाना होता है। यदि परिणाम को तुम इसके बिना भी पा सकते तो तुम क्रिया को एक ओर सरका देते और परिणाम पर कूद पड़ते, लेकिन खेल में तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि परिणाम को तुम बिना खेले पा सको तो परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। उसका महत्त्व ही प्रक्रिया के कारण है। उदाहरण के लिए, दो फुटबॉल की टीमें खेल के मैदान में है, बस एक सिक्का उछाल कर वे तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इतने बम इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना। इसे बड़ी सरलता से एक सिक्का उछाल कर तय किया जा सकता है। परिणाम सामने आ जाएगा।

रीडर्स मेल

जानलेवा शराब

बिहार में शराबबंदी जानलेवा हो चुकी है। इससे अच्छा है कि शराब से बैन हटा दीजिए। शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन गांव-गांव में जहरीली शराब बनती है। लोग पीते हैं और मर जाते हैं। शराबबंदी में पिछले 7-8 सालों में 7 लाख से ज्यादा गरीब और कमजोर लोगों को जेल में डाला गया, अभी 1 लाख से ऊपर लोग जेल में हैं। शराबबंदी से बिहार में हर गांव और पंचायत में स्मैकिये का नया वर्ग तैयार हो रहा है, जो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। यह प्रवृत्ति बेहद खतरनाक साबत हो रही है।

अभिषेक तिवारी, आईआईएमसी,जम्मू

वन्यजीवों को बचाना होगा

वन्यजीवों पर हाल ही में किए गए सर्वे से एक बात निकलकर सामने आई है कि बीते पचास वर्षों में इनकी आबादी तेजी से घटी है। लंदन की जूलॉजिकल सोसायटी लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर इंसानों के लिए गंभीर संकट पैदा करने वाली स्थितियां बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जीवों की आबादी में इस गिरावट की वजह खान-पान के सिस्टम में बदलाव और अधिक लाभ की प्रवृत्ति के साथ आक्रामक जीवों और बीमारी के कारण विश्वभर में वन्यजीवों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। ये समय चेत जाने का है। विकास के नाम पर हमने जंगलों और पहाड़ों को काटकर सड़कों और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण तो कर लिया परंतु इससे सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का हुआ है जिसकी वजह से संपूर्ण जीवों का सुरक्षा तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण पानी रोके रखने, भूजल के पुनर्भरण और वाह नियंत्रण जैसी आद्रभूमि से मिलने वाले लाभ कम हो चले हैं। मानव ने स्वार्थ के लिए वन्यजीवों के आशियाने को नुकसान पहुंचाया है। यदि हमने अपने कृत्यों पर रोक नहीं लगाई तो वन्यजीवों को हम सिर्फ फोटो और तस्वीरों में ही देख पाएंगे। यानी भविष्य में संकट गहराने वाला है।

हितेंद्र डेड़ा, दिल्ली

सराहनीय पहल

यह सराचार पढ़कर बड़ा हर्ष हुआ कि न्याय की देवी की आंखों पर से काली पट्टी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 'लेडी ऑफ जस्टिस' यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाने का निर्णय बिल्कुल सही है। भारत में न्याय की देवी आंधी कैसे हो सकती है। हमारी परंपराओं और कथानकों में तो न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता और सम्मान दिया गया है। महान सम्राट विक्रमादित्य से लेकर महाराजा हरिश्चंद्र तक से जुड़ी न्याय और सत्य की कहानियां इस देश ने कही हैं। ऐसे में अब न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाना न्याय प्रक्रिया का भारतीयता की ओर बढ़ने सम्बन्धी सुखद संकेत है। यह सब देखकर लगता है कि भारत अब अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। अब तक कानून की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, और आम धारणा थी कि कानून अंधा होता है, लेकिन कानून अब हर वक्त अपनी आंखों को खुली रखकर जो गलत है, उसे गलत और जो सही है उसे सही कहने की ताकत रखेगा। अब उसके हाथों में संविधान है।

गोपाल सोनी, धार, मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया केन्सर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-परियापुर, पुलिस स्टेशन-शहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा पद्मश्री लाल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6454
आर.एन.आई. नं. बीआईएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

10 प्रशिक्षित कार्यबल के पास ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है भारत में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में यह क्रमशः 52, 75 और 96 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए सार्थक प्रयास

हमारी उच्च शिक्षा को कौशल विकास से जोड़कर उसे समय अनुकूल बनाने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत के युवाओं के लिए एक क्वेंतरीन पहल है। यह न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि देश के उद्योगों के विकास में भी योगदान देगी। इससे युवाओं के कौशल का विकास होगा और उन्हें वास्तविक व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें

प्रतीकात्मक

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

हाल के वर्षों में भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें हाल ही में शुरू की गई एक करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी एक सराहनीय कदम है, जो न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से सहारा देगा, बल्कि उन्हें उद्योगों की वास्तविक चुनौतियों से भी रूबरू कराएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। छात्रों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव न केवल उनके पेशेवर कौशल को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें यह भी समझने में मदद करेगा कि वे किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा, हर महीने मिलने वाला पांच हजार रुपये का भत्ता युवाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा। इस योजना से देश के कौशल विकास कार्यक्रम को भी एक नई दिशा मिलेगी। भारतीय कंपनियों को कामकाज के लिए तैयार और प्रशिक्षित युवा मिलेंगे, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। यह योजना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिनके पास महंगी शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन वे कामकाजी अनुभव के माध्यम से अपने करियर को आकार देना चाहते हैं।

चुनौतियां : हालांकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना काफी महत्वाकांक्षी और लाभदायक प्रतीत होती है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे पहली चुनौती यह होगी कि इंटर्नशिप कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अभ्यर्थियों को वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान और कार्यस्थल का अनुभव प्रदान करें, न कि उन्हें केवल सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरी चुनौती क्षेत्रीय असमानताओं की होगी। यह योजना देश के शहरी क्षेत्रों में आसानी से लागू हो सकती है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के युवाओं तक इसे प्रभावी ढंग से पहुंचाना कठिन काम होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवा भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। तीसरी चुनौती, योजना की निगरानी और मूल्यांकन की होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटर्नशिप की गुणवत्ता पर नजर रखी जाए और यह केवल कागजी योजना बनकर न रह जाए। इसके लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस योजना के तहत दी जा रही इंटर्नशिप वास्तव में प्रभावी हैं या नहीं।

सरकार और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवाओं के लिए भी इंटर्नशिप के अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। इसके लिए स्थानीय उद्योगों के साथ भागीदारी की जा सकती है। इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को उनके कौशल के आधार पर स्थायी नौकरी की संभावनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। इससे योजना की प्रभावशीलता बढ़ेगी और युवाओं को लंबे समय तक रोजगार मिल सकेगा। इस योजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि कंपनियां इंटर्न को वास्तविक अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान कर रही हैं।

कौशल विकास : देश की युवा आबादी के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता बनाना जरूरी है। लेकिन कौशल विकास से जुड़ी कई चुनौतियां हैं, जिनका समाधान तलाशना सरकार और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के केवल 10 प्रतिशत कार्यबल के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है। यह आंकड़ा अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफी कम है, जहां यह क्रमशः 52, 75 और 96 प्रतिशत है, लिहाजा इस कमी को पाटने के लिए कौशल विकास मिशन को तेज करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 1.2 करोड़ से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास उपयुक्त कौशल नहीं होते। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत को हर साल तीन-चार प्रतिशत की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण देना होगा। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम की 'फ्यूचर आफ जाब्स' नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक कई वर्तमान नौकरियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है और 40 प्रतिशत नौकरियां नई होंगी। इसका मतलब यह है कि भारत को अपने कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित करने और नए कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 37 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में यह 23.3 प्रतिशत थी। इस कमी को दूर करने के लिए महिलाओं के कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे वे कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। स्ट्रेटजी एंड इकोनमिक कंसल्टेंसी फर्म अल्फाबीटा की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2025 तक डिजिटल स्किल्ड कर्मचारियों की मांग जरूरत बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को 2025 तक टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन व इंडस्ट्री डिमांड के अनुरूप नई स्किल्स सीखनी होंगी। इस समय देश में 13 प्रतिशत ही कर्मचारी डिजिटली स्किल्ड हैं।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2023 के ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 103वें रहा। यह संकेत है कि देश को अपने शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़े सुधारों की आवश्यकता है, जिससे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक वैश्विक रोजगार की 65 प्रतिशत नौकरियों में उच्चतम कौशल की आवश्यकता होगी, जो आज के श्रम बल के बड़े हिस्से के पास नहीं है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और इसके तहत युवाओं को वास्तविक व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होता है, तो यह योजना देश की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि इसके क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता होगी। तभी यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सार्थक सिद्ध होगी।

शिक्षा और रोजगार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी

हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली की एक चुनौती यह रही है कि छात्रों को डिग्री मिलने के बावजूद वे उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप रोजगार पाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते। ऐसे में यूजीसी द्वारा प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) इस समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकता है। यूजीसी ऐसे दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार कर रहा है, जिससे स्नातक पाठ्यक्रमों में अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य किया जाएगा। यह कदम न केवल युवाओं को व्यावहारिक कौशल से लैस करेगा, बल्कि उनके रोजगार की संभावनाओं को भी व्यापक बनाएगा। जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत कालेजों और विभि में इस पाठ्यक्रम को लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

अप्रेंटिसशिप एक ऐसी व्यवस्था है जो छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ उद्योग के वास्तविक अनुभव से भी जोड़ती है। यह प्रणाली छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ ही उन्हें व्यावहारिक कौशल विकसित करने का भी अवसर प्रदान करती है। छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ किसी कंपनी या संगठन में भी काम करने का अनुभव मिलता है, तो वे अपने क्षेत्र में अधिक कुशल और आत्मविश्वासी बनते हैं। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बाजार में मात्र डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। कार्यक्षेत्र में आवश्यक तकनीकी और पेशेवर कौशल रखने वाले स्नातकों की आवश्यकता है। अप्रेंटिसशिप इस दिशा में छात्रों के लिए एक सेतु का काम कर सकती है। जब छात्र अपने विषय के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़े रहते हैं, तो वे अध्ययन के दौरान ही यह समझ जाते हैं कि विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है और विभिन्न क्षेत्रों में वे अवसरों की पहचान भी कर पाते हैं। वैसे यूजीसी की प्रस्तावित एईडीपी सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कालेज और विश्वविद्यालय किस प्रकार से इस अप्रेंटिसशिप कोर्स को अपने वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को न केवल आवश्यक ढांचा तैयार करना होगा, बल्कि विभिन्न उद्योगों के साथ भी साझेदारी स्थापित करनी होगी।

यूजीसी का यह निर्णय कौशल विकास को दिशा में एक सार्थक कदम है। यह सही समय पर लिया गया एक ऐसा निर्णय है, जो देश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्रोग्राम शिक्षा को और अधिक उपयोगी व प्रभावी बनाएगा, जिससे न केवल छात्र, बल्कि उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था भी लाभान्वित होगी। यह एक ऐसा माडल है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास को प्राथमिकता देगा और छात्रों को रोजगार योग्य बनाएगा। यह निर्णय छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाली दिशा में एक ठोस कदम है। शिक्षा व रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करने का निर्णय हमारे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देगा और हमारे युवाओं को एक आत्मनिर्भर और कुशल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। (कैलाश विश्नोई)

खरी-खरी

पार्टटाइम सेवक

मिथलेश कुमार मिश्रा

कहने को तो साहब सरकारी सेवक हैं, लेकिन पार्टटाइम वाले। फुलटाइम में वह साहित्य साधन या आनलाइन बीहियों के अवलोकन में तल्लीन रहते हैं। जनाब की उपस्थिति अपने सरकारी कार्यालय या विद्यालय, महाविद्यालय से ज्यादा इंटरनेट मीहिया प्लेटफार्म पर दिख जाती है। यदि आफलाइन मोड में कार्यस्थल पर उपलब्ध भी रहते हैं, तो मोबाइल, लैपटाप आदि के माध्यम से इंटरनेट मीहिया प्लेटफार्म पर ही विचरण करते रहते हैं। वहीं साहित्य प्रेम कहें अथवा छपास की लिप्सा या फिर नयनाभिराम की अभिलाषा, जनाब के दैनिक जीवन का लगभग दो तिहाई समय फेसबुक, इंस्टा, एक्स अथवा वाट्सअप पर ही व्यतीत होता है।

यदि इंटरनेट मीहिया अस्तित्व में नहीं आया होता, तो साहब का दैनिक इंटरनेट डाटा का 90 प्रतिशत हिस्सा बरबाद हो ही जाता। यह और बात है कि ऐसे पार्टटाइम सरकारी सेवक तथा फुलटाइम साहित्यकार, ब्लागर, इंफ्लुएंसर, रील्स, मीम्स, यूट्यूब व्यूअर्स होने के कारण जनाब को डाटा लोन लेना पड़ जाता है अथवा डाटा उपभोग के लिए विभागीय बाइ-पाइ की शरण में जाना पड़ जाता है। कई बार तो उन्हें डेटा का प्लान भी रिचार्ज करवाना पड़ता है।

इंटरनेट मीहिया में घोर आस्था रखने वाले सरकारी सेवक, खासकर शिक्षक या व्याख्याता जिन्हें साहित्यकार होने का आंशिक भ्रम, वहम या अहम है, इंटरनेट मीहिया के प्रति उनकी भक्ति देखते ही बनती है। इनके प्रोफाइल पर प्रत्येक कार्य दिवस में घूमने, लिखने से लेकर छपने आदि तक का अपडेट तो रहता है, लेकिन सरकारी वेतन के एवज में किए गए सरकारी कार्यों या फिर दायित्वों का लेखा-जोखा तलाशने से शायद ही मिल पाता है।

प्रत्येक घंटा इंटरनेट मीहिया प्लेटफार्म्स पर अपना साहित्यिक अपडेट करने के व्यस्त शेड्यूल में से जनाब आजीविका अथवा सर्विस के लिए किस प्रकार और कितना समय निकाल पाते हैं, यह किसी रहस्य से कम नहीं। कार्य स्थल से नदारद और फेसबुक पर बरामद होने वाले ऐसे पार्टटाइम सरकारी सेवक एवं फुलटाइम इंटरनेट मीहिया सेवी की श्रम साधन निश्चित रूप से स्तुति योग्य है।

पोस्ट

परिणाम के देश भी अजब पखाड़ी है। वे दूसरे देशों को नष्ट करते हैं, वहां तख्तपलट कराते हैं, वहां के नेताओं की हत्या करते हैं, ग्वाटनामो वे में कैदियों को सबसे अमानवीय परिस्थितियों में रखते हैं, और फिर हमें मानवाधिकारों पर लेक्चर देते हैं और एक अपराधी की कथित हत्या पर हंगामा करते हैं।

प्रकाश सिंह@singh_prakash

हिंदुस्तान के कुछ लोग मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा दो एक पूर्व अधिकारी विकास यादव के नाम का पोस्टर छपाने पर खुशी मना रहे हैं। वे लोग तब दुखी हो जाएंगे, जब भारत में मौजूद किसी पूर्व सीआइए अधिकारी का पोस्टर छप जाएगा। लगता है इनके लिए दल बड़ा है, देश नहीं।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जिस दिन नवाज शरीफ भारत से संबंधों को लेकर कह रहे थे कि '75 साल गंवा दिए, अगले 75 साल न गंवाएं', उसी दिन पाकिस्तान ड्रोन के जरिये भारत में आरडीएक्स भेज रहा था। एक तरफ रिश्ते सुधारने की मांग, दूसरी तरफ बेगुनाहों की जान लेने की साजिश। दोमुंही बातें करना कोई पाकिस्तान से सीखे।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत — कल का परिणाम

बेंगलुरु टेस्ट में टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का सोचिए तथा कौन फैक्टर भारी रहा?

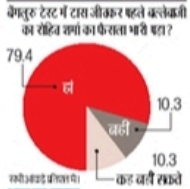

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

भारत रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा को चार से घटाकर दो महीने कर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पहले नसरुल्ला गया गया अतः सिनवार,
तेल देखते जाइए और तेल की धार।
और तेल की धार आगे निसरुल्ले छेड़ा,
जो इजरायल देता बहुत है समुमुए एड़।
दुश्मन के संग मर रहा नहले पर दहले,
कब्जा पीछे वार रहा लगता रहीखो पहले!

- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

शराबबंदी में नीतीश को नहीं मिल रहा तंत्र का पूरा साथ

अरुण अतोष
रूपस मूरो ब्यूरो, बिहार

बिहार में शराबबंदी कानून के साथ कई आयाम जुड़े हुए हैं। इसे जिस वर्ग के हित में बनाया गया है, वह आम आबादी है। इसका बड़ा हिस्सा इस कानून को अच्छा मानता है। समर्थन करता है। एक छोटा हिस्सा इसका विरोध करता है। इसे नापसंद करता है। यह नापसंदगी शराबखोरों में प्रकट होती है। जहरीली शराब से मौतें होती हैं। अभी सारण प्रमंडल के तीन जिलों- छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। तीन दिनों के भीतर 50 से अधिक लोग मर चुके हैं। लगभग 80 लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ और की जान जा सकती है। जहरीली शराब से मौतें होती रहती हैं। इक्का-दुक्का मौतें गिनती में नहीं आती हैं। वर्ष 2016 के शराबबंदी के मूल कानून में जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजे का प्रविधान नहीं किया गया था। दो साल पहले जहरीली शराब से मौत प्रमाणित होने पर मृतक के स्वजनों को चार लाख रुपये मुआवजे का प्रविधान किया गया है। दुर्घटना से वह बदलाव भी छपरा में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों को लेकर किया गया था। आज भी वहां के मृतकों के स्वजनों के लिए मुआवजे की मांग हो रही है।

जहां तक आम आबादी का प्रश्न है, वह शराबबंदी के पक्ष में है। क्योंकि शराब पीकर हंगामा और मारपीट करने की खबरें नहीं आ रही हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीते आठ वर्षों में घरेलू हिंसा में कमी आई है। शराब जनित बीमारियों का आंकड़ा भी कमजोर पड़ा है। लेकिन, कई तरह की नई बीमारियां भी प्रवेश कर गई हैं। उनमें प्रमुख है शराब की तस्करी। यह गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब की उपलब्धता दिनों-दिन आसान हो रही है। बीतल, पाउच और ट्रेठा पैक में यह आसानी से उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जब शराब की हर जगह उपलब्धता की बात करते हैं तो उनके कथन का कोई अधिकारिक विरोध नहीं करता है। बिहार का हर आदमी कहता है कि शराब आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य की बड़ी आबादी शराबबंदी कानून का विरोध कर रही है और वह इसे हटाने के पक्ष में है।

सारन के एक गांव में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद वहां उमड़ी भीड़। फाइल

नई बनी जनसुराज पार्टी ने शराबबंदी कानून को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो आधे घंटे के भीतर इस कानून को समाप्त कर देंगे। पीके ने यह घोषणा अपने के बीच की। उधर जनसुराज के अध्यक्ष और भारतीय विदेश सेवा के अवकाशप्राप्त अधिकारी मनोज भारती हाल में भोजपुर गए थे तो उन्हें इस मुद्दे पर जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि शराबबंदी कानून को मिल रहे जनसमर्थन को देखते हुए प्रशांत किशोर धीरे-धीरे अपनी घोषणा से पीछे हटेंगे। क्योंकि अगर वह लंबे समय तक इस पर डटे रहे तो उन्हें शराब लाबी के धन पर राजनीति करने के आरोप का भी सामना करना पड़ सकता है। आप बिहार के किसी राजनेता से पूछें तो निजी बातचीत में वह बताएंगे कि शराबबंदी कानून का असर कम हो रहा है। इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन, यह सब उन्हें रिकार्ड पर बोलने के लिए कहें तो पीछे हट जाएंगे। जीतनराम मांझी जैसे एनडीए के बड़े नेता के अलावा विपक्षे राजद और कांग्रेस के नेता खुले तौर पर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हैं। समीक्षा से उनका आशय यह है कि राज्य सरकार इस मामले में गुजरात के माडल को अपना ले। यानी शराब की खरीद के लिए परमिट सिस्टम लागू कर दे। राज्य सरकार की ओर से इस तरह के सुझाव पर कोई उत्तर नहीं मिला है। हां, मूल कानून में कई बार संशोधन कर उसे थोड़ा हल्का किया गया है। पहली बार शराब पीने पर जेल भेजने के प्रविधान को समाप्त कर उसे जुर्माने में बदल दिया गया है।

प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर शराबबंदी कानून सख्ती से और पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप में भी दिया जा सकता है। संक्षिप्त, सटीक परंतु अप्रिय लगने वाला उत्तर यह हो सकता है कि सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ कर अधिकांश लोग इस कानून का दिल से सम्मान नहीं करते हैं। उन लोगों के मन में भी इस कानून के प्रति यथेष्ट सम्मान नहीं है, जिन्होंने शराब न पीने की शपथ ली है। उन सरकारी मुलाजिमों के मन में भी नहीं है, जिन्हें शराब न पीने की सर्वजनिक शपथ दिलाई गई है। सही तस्वीर यह बनती है कि इस मामले में नीतीश कुमार के पक्ष में भले ही राज्य की बड़ी आबादी हो, लेकिन वह तंत्र नहीं है, जिस पर शराबबंदी कानून को लागू करने की जवाबदेही है।

मंथन

पराली निस्तारण के उपाय

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीरता फिर धीरे-धीरे बढ़ रही है। उपाय के तौर पर प्रदूषण के सभी कारकों पर नियंत्रण के साथ ही पराली प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद

पराली का निस्तारण एक गंभीर समस्या है। पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इस बारे में दावे भले बराबर किए जाएं, लेकिन हकीकत में यह समस्या हर साल और विकराल होती जा रही है। दुखदाई बात यह है कि सरकारें इस बाबत तब होश में आती हैं, जब इस समस्या के चलते वायु प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है।

देख जाए तो पराली जलाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा और पंजाब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भयावह वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है। ये महीने यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आते हैं, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों द्वारा इसे रोकने की दिशा में किए गए सारे प्रयास, अभियान और किसानों को जागरूक करने के सभी कदम बेमानी साबित हो जाते हैं। दुर्भाग्यस्वरूप वायु प्रदूषण की गंभीरता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और सरकारें इसके सामने बेबस नजर आती हैं। यह सब तब होता है, जब पराली जलाने पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बाबत गंभीर चिंता जाहिर कर चुका है कि यह कैसे प्रबंधन है कि प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रदूषण की रोकथाम के दावे हवा-हवाई हैं।

जहरीली हवा में सांस : राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते यहां के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में इस कारण बड़ी संख्या में लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। नतीजन पहले से ही अस्थमा से परेशान लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा बन जाता है। ऐसे हालात में अस्थमा के रोगियों का बढ़ना खतरनाक संकेत है। वैसे भी मौसम में आ रहे बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजाब में अभी तक पराली जलाने की घटनाओं में नौ गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि पंजाब में इस बार धान की कटाई के बाद 200 लाख टन पराली बचेगी, जबकि राज्य का लक्ष्य लगभग 20 लाख टन पराली के प्रबंधन का ही है। जाहिर है, शेष पराली प्रबंधन के अभाव में जलाई ही जाएगी। वैसे पराली निस्तारण के लिए पंजाब सरकार ने 58 कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसके पास पराली का भंडारण करने के लिए जमीन ही नहीं है।

पर्यावरण स्वच्छता : पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना केंद्र, राज्य, समाज और लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसे सभी को ईमानदारी से निभाहना चाहिए। लेकिन इसमें हम विफल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि खुस तौर पर जब सर्दियों में आसमान धुंध और विषाक्त गैसों से घिरा होता है, केवल उस समय ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाए। पूरे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बीते बरस दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और पराली से कंपोस्ट खाद बनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से दोहरा लाभ होगा। खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी और दूसरी ओर किसान इस खाद का उपयोग कर बेहतर और रसायन विहीन पैदावार हासिल कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में महत्ता प्राप्त होने पर पराली का होगा समुचित प्रबंधन। फाइल

ठोस कारकों की भूमिका : वायु प्रदूषण में पराली की अहम भूमिका है, लेकिन सड़कों की धूल एवं वहां फैले कूड़े व बायोमास का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इससे वातावरण में जहर के काकटेल का निर्माण होता है। वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एयरोसेल का निर्माण, बिजलीघरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन आक्साइड तथा कृषि कार्य से पैदा होने वाले अमोनिया के मेल से होता है। लगभग 23 प्रतिशत वायु प्रदूषण की वजह यह काकटेल ही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जायजा लें तो पता चलता है कि धूंध का 20 प्रतिशत उत्सर्जन दिल्ली के वाहनों से, 60 प्रतिशत दिल्ली के बाहर के वाहनों से तथा 20 प्रतिशत के आसपास बायोमास जलाने से होता है।

इस संदर्भ में किए गए अनेक हालिया शोध-अध्ययनों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वायु प्रदूषण की समस्या किसी युद्ध की विभीषिका की आशंका से कम नहीं है। इसलिए विकास का ढांचा उसी स्थिति में कारगर हो सकता है, जब वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान हम अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निकालने का प्रयास करें।

****

दैनिक जागरण
खुशी का सबसे बड़ा रहस्य त्याग है

जहरीली शराब का कहर

बिहार के सिवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से अब तक लगभग 50 लोगों की मौत शराबबंदी की पोल खोलने के साथ यह भी बयान कर रही है कि राज्य सरकार और उसका तंत्र अवैध तरीके से शराब के निर्माण और उसकी बिक्री को रोक पाने में विफल है। जहरीली शराब के चलते इतने अधिक लोगों की मौत इसलिए गंभीर चिंता की बात है कि बिहार में इसके पहले भी जहरीली शराब कई लोगों की जान ले चुकी है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि जहरीली शराब से मौतों के बाद शराब माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। यदि ड्रोन कैमरों की मदद से शराब की भट्ठियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का अभियान पहले से चल रहा होता तो शायद इतने अधिक लोग जहरीली शराब के कारण काल के गाल में नहीं समाते। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जहरीली शराब के सेवन के बाद जिनकी जान बच गई है उनमें से कुछ अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं।

बिहार सरकार को कम से कम अब तो इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी शराबबंदी सफल नहीं हुई है। बिहार में भी यह नाकाम है। कहने को राज्य में शराबबंदी है, लेकिन वह हर जगह उपलब्ध है और यहां तक कि उसकी होम डिलीवरी भी होती है। स्पष्ट है कि अवैध तरीके से शराब बेचने वालों ने अपना एक सुगठित तंत्र विकसित कर लिया है। समस्या केवल यह नहीं है कि दूसरे राज्यों से चोरी-छिपे शराब लाकर बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं। समस्या यह भी है कि शराब की वैध बिक्री से राज्य सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का जो राजस्व मिलता, वह अवैध कमाई के रूप में शराब माफिया और उन्हें संरक्षण देने वालों की जेबों में जा रहा है। निःसंदेह शराबबंदी न होने के बाद भी गुपचुप रूप से शराब बनाने-बेचने का काम हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस तथ्य की अनदेखी कर दी जाए कि शराबबंदी अवैध तरीके से शराब बनाने वालों को फलने-फूलने का मौका देती है। वे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के फेर में घटिया या फिर नकली शराब बनाते हैं, जो कई बार जहरीली हो जाती है। ऐसे तत्व तभी सक्रिय हो पाते हैं, जब उनकी अनदेखी की जाती है। जहरीली शराब कांड के बाद शराब की कई अवैध भट्ठियां और बनी-अधबनी शराब मिलने से इसकी पुष्टि हो होती है कि इसकी निगरानी सही तरह नहीं हो पा रही थी कि कहीं गुपचुप रूप से घटिया और अंततः जानलेवा साबित होने वाली शराब का निर्माण तो नहीं किया जा रहा है? इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि बिहार में बाहर से लाकर शराब बेचने वाले भी सक्रिय हैं और उसे अवैध तरीके से बनाने वाले भी।

महिला नीति

उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महिला नीति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। राज्य गठन से लेकर अब तक के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो महिलाएं ही सर्वेसेवियों के लिए घास से लेकर घर तक का बोझ उठाए हुए हैं। यहां पलायन से गांव पूरी तरह खाली नहीं हुए हैं तो इसका मुख्य कारण महिलाएं ही हैं। वे यहां रह रही हैं और खेतों को भी आबाद कर रही हैं। सरकार महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकारी सेवाओं में उन्हें 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। बावजूद इसके महिलाओं का एक बड़ा तबका ऐसे सभी तरह के लाभ से वंचित है। इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए सरकार महिला नीति पर काम कर रही है। नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति और कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों का संज्ञान लिया जा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर रोक के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बाहरों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की योजना बनाई जा रही है। देह व्यापार में धकेली गई महिलाओं के पुनर्वास एवं स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कदम महिलाओं के हितों के साथ ही उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। जरूरत इस नीति को समय से धरातल पर उतारने की है। नीति में जिन बिंदुओं का उल्लेख हो, उन पर गंभीरता से काम हो। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बनाना भी आवश्यक है। उम्मीद है राज्य स्थापना दिवस तक महिला नीति को धरातल पर उतार दिया जाएगा।

> मातृशक्ति को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए महिला नीति का अस्तित्व में आना जरूरी है

अपने ही क्षत्रपों से पस्त कांग्रेस

राज कुमार सिंह

राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने क्षत्रपों की कठपुतली बन गई है, जो अपने हितों को पार्टी हित से ऊपर रखते हैं

हरियाणा की हार से हतप्रभ राहुल गांधी गुस्से में बताए जाते हैं। समीक्षा बैठक में उनकी इस टिप्पणी की बहुत चर्चा है कि नेताओं ने 'अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझा', पर क्या ऐसा पहली बार हुआ? राहुल गांधी 2004 में चुनावी राजनीति में आए। संयोगवश उसी साल कांग्रेस का केंद्रीय सत्ता से दस साल का वनवास समाप्त हुआ। 'शाइनिंग इंडिया' की चकाचौंध में डूबी भाजपा की अगुआई वाले राजग को मतदाताओं ने सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता परिवर्तन इस मायने में चौंकाने वाला रहा कि तब भाजपा और राजग के नेतृत्व शीर्ष पर अटल बिहारी वाजपेयी सरीखा व्यक्तित्व था, जबकि कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ थी, जिन्हें अपनी पार्टी में भी लंबे सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तब भी केंद्रीय सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने जमीन पर कुछ तोप नहीं किया था, पर सोनिया ने चुनावी गठबंधन की गजब बिसात बिछाई। सक्रिय राजनीति का पहला दशक राहुल गांधी के लिए 'आस इज बेल' वाला रहा, पर उसके बाद तो कांग्रेस और कांग्रेसियों की तमाम कमजोरियां बेनकाब होती गईं। ऐसे में सवाल है कि स्वयं राहुल ने उन्हें दूर करने के लिए क्या किया है?

यदि राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित हार से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नेता अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझते हैं, तब तो सबाल उनकी राजनीतिक समझ पर भी उठ सकता है। मंडल-कमंडल के राजनीतिक ध्रुवीकरण के बाद से देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश-बिहार में कांग्रेस हाशिये पर है। देश में दशकों तक शासन करने वाले दल की ऐसी दुर्गति कई सवाल खड़े करती है। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय के पैरोकार क्षेत्रीय दलों और हिंदुत्ववादी भाजपा के बीच हुए ध्रुवीकरण से कांग्रेस अप्रासंगिक होती गई, लेकिन आखिर अन्य राज्यों में अपनी पराजय कथा के लिए वह किसे दोष देगी? राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने ही क्षत्रपों की कठपुतली बन गई है, जो हमेशा अपने हितों को पार्टी हित से ऊपर रखते हैं और आलाकमान को आंखें दिखाने में भी संकोच नहीं करते।

गुटबाजी कांग्रेस का चरित्र रहा है। जब तक आलाकमान सर्वशक्तिमान था, गुटों को नियंत्रित सक्रियता से अंततः पार्टी मजबूत होती थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस के ऐतिहासिक पराभव के बाद क्षत्रप अपनी मनमानी करने लगे। अपने और परिवार के अलावा किसी का पनपना इन्हें गवारा नहीं। चाहे इस कवायद से विरोधी दल की मदद ही क्यों न हो। कांग्रेस के पतन में अंतर्कलह की एक बड़ी भूमिका रही है, पर यदि पिछले एक दशक पर ही फोकस करें तो पाएंगे दिल्ली अपूर्ण राज्य ही सही, पर वहां कांग्रेस बेहाल है। 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति शून्य है। यह हाल वहां है, जहां 2013 से पहले कांग्रेस लगातार 15 साल सत्ता में रही। 15 साल की सरकार के कामकाज के बल पर कांग्रेस को बहुत मजबूत होना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि वह संगठन और जनाधार, दोनों स्तर पर खोखली होती गई? सत्ताकाल में दिल्ली कांग्रेस का अंतर्कलह राहुल गांधी को याद होगा ही। तब जमीन से जुड़े नेताओं की अगली पौढ़ी को आगे लाया गया होता तो आज चुनाव जीतने लायक चेहरों का अकाल दिल्ली कांग्रेस में नहीं होता।

2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतकर राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया था, पर उसके बावजूद वहां कांग्रेस मजबूत हुई या कमजोर? तीनों राज्यों में सरकार बनने के साथ ही अंतर्कलह के जो बीज पड़े, उनकी फसल कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में काटनी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घेरे पर दांव लगाने के बजाय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरीखे पुराने क्षत्रपों के चंगुल में फंसे रहने का परिणाम यह हुआ कि बगावत के चलते 2020 में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर गई। सचिन पायलट को बगावत से रोक कर कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में तब तो सरकार बचाने में सफल रहा, पर पिछले साल विधानसभा चुनाव में उसकी विदाई हो गई। सत्ता में वापसी की उम्मीद तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कर रही थी, पर छत्तीसगढ़ भी गंवा बैठी, जहां उसे तमाम चुनावी पंडित जिता रहे थे। खुला रहस्य है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस के पराभव का कारण क्षत्रपों का आपसी टकराव रहा, जिसके लिए आलाकमान भी कम जिम्मेदार नहीं। आखिर आलाकमान सिंधिया, पायलट और टीएस सिंहदेव से किए वायदे क्यों पूरे नहीं कर पाया? लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः अशोक गहलोत, दिग्विजय-कमलनाथ की जोड़ी और भूपेश बघेल को उसी तरह कांग्रेस की 'फ्रेंचाइजी' दे दी गई है, जैसे कभी दिल्ली में शीला दीक्षित को दी गई थी। हरियाणा का हाल भी वैसा ही है। दस साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधारवाले नेता बन गए, लेकिन उनकी चुनावी सीमाएं बार-बार उजागर भी होती रहीं। इसके बावजूद आलाकमान ने हरियाणा के क्षत्रपों में सम्नवय बिठाने या उन्हें अनुशासित करने की कोई गंभीर पहल नहीं की। नतीजतन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे नेता पार्टी छोड़ गए। एक दशक से भी ज्यादा समय से हरियाणा में कांग्रेस संगठनविहीन है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद सफाई दे गई कि गुटबाजी और गलत टिकट वितरण की वजह से कांग्रेस हारी, पर 2024 के चुनाव में तो हुड्डा को 'फ्री हैंड' था। उन्हें की पसंद उत्तरप्रदेश अध्यक्ष थे तो 90 में से 72 टिकट भी उन्हें के कहने पर दिए गए। फिर कांग्रेस क्यों हार गई? स्पष्ट है कि भारत जैसे बहुलतावादी देश में किसी एक नेता या वर्ग पर दांव लगा कर चुनावी रण नहीं जीता जा सकता, बल्कि ऐसा करने से क्षत्रपों में निजी हितों को पार्टी हित से ऊपर रखने की मानसिकता मजबूत होने लगती है। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना बताते हैं कि क्षत्रपों पर नियंत्रण और सामूहिक नेतृत्व ही जीत की कुंजी है। अब जबकि राहुल गांधी यह समझ भी चुके हैं, देखना होगा कि वह कांग्रेसी क्षत्रपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने का साहस जुटा पाते हैं या नहीं?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

अवधेश राजपूत

परिवार में भरोसे का दरकता आधार

क्षमा शर्मा

संबंधों में हिंसा तो मामूली बात है, लेकिन यह विचार कहां से आ रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता

हाल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक घटना सामने आई। एक महिला को अपनी 17 साल की लड़की का चाल-चलन पसंद नहीं था। लड़की कुछ महीने पहले एक लड़के के साथ चली गई थी। फिर वापस आ गई थी। महिला ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो उसे उसकी मौसी के घर फर्रुखाबाद भेज दिया। वहां उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई। मौसी के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने लड़की की मां को सूचित किया कि वह अपनी लड़की को ले जाए। मां ने उससे निजात पाने की ठान ली। उसने एक आदमी को सुपारी दी कि अगर वह उसकी लड़की को ठिकाने लगा देगा, तो वह उसे पचास हजार रुपये देगी। यह वही आदमी निकला, जिससे लड़की की दोस्ती थी। उसने लड़की को सारी बात बता दी, तो लड़की ने कहा कि अगर वह उसकी मां को खत्म कर देगा, तो वह उससे शादी कर लेगी। बस उस भाड़े के हत्यारे ने मां को मार डाला। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं।

इस घटना के सामने किसी फिल्म की कहानी भी फीकी लगती है। सवाल है कि आखिर समाज से डरकर या कथित बदनामी के भय से मां ने अपनी बेटी की ही हत्या क्यों करानी चाही? क्या मां ने यह सोचा कि यदि वह अपनी बेटी की हत्या करा दी, तो वह भी कानूनी शिकंजे में फंसेगी? इसी तरह क्या हत्यारे ने यह सोचा कि अगर वह मां को मारेगा तो उसका क्या होगा? लड़की भी यह नहीं सोच सकी कि जो वह कराने जा रही है, उसका परिणाम क्या हो सकता है? जब अपने ही अपनों को मारने की साजिश रचें, इसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाएं तो यह बहुत डरावना हो जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ही ऐसी घटनाओं पर नजर पड़ती है। वे खबर के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे इसी साल जनवरी में गोवा में एक स्टार्टअप की सीईओ को अपने चार साल के बेटे की हत्या में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक लड़के ने अपनी नानी की हत्या सांप से कटवा कर करवा दी। उसने एक सपेरे की मदद ली और उसे पैसे भी दिए। दरअसल नाती को पता था कि नानी ने एक करोड़ रुपये का बीमा करवाया है। नाती वह रकम लेना चाहता था। पुलिस ने नाती, सपेरे और बीमा एजेंट को पकड़ा। पिछले साल अगस्त में झांसी जिले में एक लड़के ने अपने माता-पिता को प्रेशर कुकर से हमला करके मार डाला था। लड़के को पबजी खेलने का शौक था और माता-पिता इसके लिए मना करते थे। इसी तरह दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला ने अपने डेढ़ साल के बेटे को गला घोंटकर मार डाला। महिला को आशंका है लोग ताने देते थे कि बच्चा उसके पति का नहीं है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से इस बात को लेकर महिला का कई बार झगड़ा भी हुआ था। कारा महिला को वह सब न सुनना पड़ता, तो शायद उस डेढ़ साल के मासूम की जान बच जाती।

ऐसी भी घटनाएं अक्सर ही पढ़ने-सुनने में आती हैं कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए पति की हत्या करवा दी। कहीं पति पत्नी या ब्वायफ्रेंड गलफ्रेंड से छुटकारे के लिए ऐसा करते हैं। बीते दिनों ऐसी ही एक घटना हरियाणा में घटी थी। वहां एक महिला और पुरुष के संबंध बन गए थे। महिला के पति ने तो तलाक की हामी भर दी, लेकिन उस पुरुष की पत्नी उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। महिला ने अपने मित्र से कहा कि जब तक वह अपनी पत्नी से छुटकारा नहीं पाएगा, तब तक वह उससे शादी नहीं करेगी। इसके लिए दोनों ने योजना बनाई। वह आदमी अपनी पत्नी को पहाड़ी जगह पर ले गया और वहां से धक्का दे दिया। सास-ससुर से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत बार ऐसे किया गया है।

वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक लड़की ने तो ब्वायफ्रेंड से मिलने से मना करने पर पूरे परिवार को ही जहर देकर मार दिया था। इसी तरह एक महिला ने अपने ब्वायफ्रेंड की खातिर अपने दो बच्चों को जिंदा जला दिया था। संबंधों में हिंसा तो मामूली बात है, लेकिन आखिर कानून पर इतना अविश्वास क्यों है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि अंततः अपराधी पकड़े ही जाते हैं। कई बार तो वर्षों बाद। अफसोस की बात यह है कि तकनीक के विस्तार ने ऐसी घटनाओं को खूब बढ़ाया है। हिंसा से भरे वीडियो अपलोड करना इन दिनों मामूली बात हो चली है। वे खूब देखे भी जाते हैं। इन पर कोई रोक-टोक दिखाई नहीं देती। किसी को डर भी नहीं लगता। यह देखने में आ रहा है कि अब रिश्तों की मर्यादा की पहले जैसी परवाह नहीं की जाती। जिस परिवार पर हम इतना विश्वास करते हैं कि आखिर उसमें विश्वास का हनन इतना क्यों हो गया है? अगर कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार के लोग ही बचाने आते हैं। ऐसे में परिवार के लोग ही जान के दुश्मन बन जाएं तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? ऐसी घटनाएं जानने के बाद तो जैसे भरोसे का आधार भरभराकर टूट जाता है। पैसे, झूठे सम्मान की चाहत, किसी दूसरे आदमी या किसी दूसरी स्त्री की तरफ भागना, माता-पिता का बच्चों के संबंधों पर रोक-टोक आदि ऐसे मुद्दे हैं, जहां आज मनुष्य अपना विवेक खो दे रहा है। इसमें स्त्री-पुरुष कोई पीछे नहीं है। समझ में नहीं आता कि जाएं कहां? जब अपने ही भक्षक बन जाएं तो जा भी कहां सकते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

खामखाह का भय। प्रेट

ऊर्जा

सम्मोहन

सम्मोहन का अर्थ है- विमूर्छता। यह अवचेतन मन की एक विशिष्ट दशा है, जिसके अधीन जीव आत्मदश को विस्मृत कर स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। सात्विक श्रद्धा ही प्रगढ़ होकर सम्मोहन का रूप धारण करती है। अतः सम्मोहन सात्विक वृत्तियों से उत्पन्न श्रद्धा का उत्कृष्ट परिणाम है। गोपियों एवं ग्वालबालों का भगवान श्रीकृष्ण के प्रति सम्मोहन ऐसा ही था। वे उनके नैसर्गिक रूप-सौंदर्य और लीकोपकारी लीलाओं से स्वतः आकृष्ट होते थे। यही भगवान श्रीराम के चरित्र में भी है। उनके प्राकट्य पर 'मास दिवस कर दिवस भा मरसु न जानइ कोइ' कहकर गोस्वामी जी ने भगवान श्रीराम के सम्मोहन को ही प्रकट किया है। मां का उनके मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करना, धनुषयज्ञ में उपस्थित राजाओं एवं नर-नारियों का अपने भावानुसार श्रीराम को विविध रूपों में देखना जैसे प्रसंग सम्मोहन के उदाहरण हैं।

अवचेतन अवस्था में पहुंचकर भक्त जब भाव की उच्चतम दशा को प्राप्त कर लेता है। तब शरीर रोमांचित और पुलकित हो जाता है। नेत्रों से अश्रुधारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। समय कुछ पल के लिए मानो ठहर सा जाता है। श्रीराम को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अधिकांश लोगों ने इसका अनुभव भी किया था। बेसुध कर देने वाले ये पल सामान्य नहीं होते। यह कल्पना की नहीं, भावदशा की पराकाष्ठा होती है। वस्तुतः अंतरात्मा के तार हमारे पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रेमातिरेक की आवश्यकता होती है। जब लौकिक प्रेम के अतिरेक में प्रेमी आत्मदशा को विस्मृत कर देता है, तो अलौकिक प्रेम की बात ही क्या? अतिशय प्रेम ही तादात्म्य स्थापन का कारण होता है। जब श्रद्धा और भक्ति का सैलाब सारे तटबंध तोड़कर हमारी मनस्चेतना के तार उनसे जोड़ देता है तो हम भाव-विभोर हो जाते हैं। यही सम्मोहन की स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, जिसे हर कोई अनुभव कर सकता है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

काल बनती अवैध शराब

योगेश कुमार गोयल

राज्य सरकारें जहरीली शराब के फलते-फूलते अवैध कारोबार को लेकर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकतीं

बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया है, जिससे दर्जनों घरों में मातम छा गया है। नकली और जहरीली शराब से कभी पंजाब में तो कभी बिहार में, कभी तमिलनाडु में, कभी झारखंड तो कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश तो कभी कर्नाटक में दर्जनों लोगों की मौत की खबरें विचलित करती रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि देश की सरकारों के लिए यह कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता, न ही कभी यह चुनावी मुद्दा बनता है। चिंता का कारण यही है कि जहरीली शराब पीने के कारण अक्सर लोगों के मौत के मुंह में समाने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन कुछ दिन हो-हल्ला होने के बाद सब शांत हो जाता है और इस अवैध धंधे पर लगाम लगाने के कोई गंभीर प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किए जाते। जहरीली शराब पीने के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती हैं और सैकड़ों परिवार उजड़ जाते हैं, इसीलिए राज्य सरकारें जहरीली शराब के फलते-फूलते इस अवैध कारोबार को लेकर अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकतीं।

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अवैध रूप से बनाई जाने वाली नकली अथवा जहरीली शराब से प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मौत होती है। भारत में 2016 से 2020 के बीच अवैध और नकली शराब पीने से 6172 लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2016 में 1054, 2017 में 1510, 2018 में 1365, 2019 में 1296 और 2020 में 947 लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई थी। कच्ची शराब में कई ऐसे रसायन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और इसे लंबे समय तक खाने से कई बार इसमें कीड़े भी हो जाते हैं, जो शराब के जहरीली होने का कारण बनते हैं। कई बार यह नपुंसकता एवं नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव डालती है। देसी शराब को ज्यादा नशीली बनाने के चक्कर में यह जहरीली हो जाती है।

अवैध शराब का धंधा इसीलिए तेजी से फलता-फूलता है, क्योंकि सस्ती शराब पाने के लालच में लोग खुद-ब-खुद इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं, लेकिन इसके कारण कोई अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठता है तो कोई अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर डालता है। नकली शराब पीकर मरने वाले ज्यादातर गरीब तबके के लोग ही होते हैं, जो कम पैसे में नशे की पूर्ति के लिए ऐसी शराब खरीदते हैं, लेकिन जहरीली शराब से उनकी मौत होने पर उनके परिवार के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाने की मांग होती रही है, जो दूसरों के लिए भी नजीर बने। जब तक इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों पर हाथ नहीं डाला जाएगा, तब तक जहरीली शराब लोगों को बेमौत मारती रहेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विकल्प की तलाश में किसान

'कानूनों से नहीं रुकेगा पराली का जलाना' शीर्षक से लिखे आलेख में पंकज चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सख्त कार्रवाई करने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों को निर्देशित किया है। लेखक ने पराली जलने पर बायुमंडल को प्रदूषित करने वाले अवयवों जैसे सल्फर डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड तथा राख आदि का जिक्र आंकड़ों के साथ बहुत अच्छा किया है। पहले तीन अवयव गैस हैं, जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, परंतु जो राख खेत में बचती है वह कुछ पोषण तत्वों की बढ़ाती है जिसमें पोटाश प्रमुख है। आलेख में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि फसल अवशेष जलाने से भूसाछह की छह इंच परत से लाभदायक सूक्ष्मजीव जल कर भस्म हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। किसान पराली को अपने हिसाब से भूमि पर फैलाकर जलाते हैं। धान के खेत में नमी रहती है और पराली जलने की प्रक्रिया बहुत कम समय जैसे पांच या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इतने अल्पकाल में सूक्ष्मजीवों को बहुत हानि नहीं होती है। अगर कुछ हानि होती भी है तो जोताई के उपरांत सब मिट्टी ऊपर-नीचे की मिल जाती है और मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या सामान्य स्तर पर पहुंच जाती है। पराली जलने से एक और बात होती है कि कुछ विशेष सूक्ष्म जीव जो मरणासन्न होते हैं, ऊष्मा पाकर सक्रिय हो जाते हैं। खरपतवार के बीज जो फसल को नुकसान करते हैं, जल जाते हैं। बास्तव में गेहूं की सभस्त खेतों में बोआई करने के लिए किसान खेत को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए धान की पराली जलाते हैं। किसान इसका व्यावहारिक हल खोज रहे हैं। यदि उपयुक्त विकल्प मिल सका तो ही पराली जलना रुकेगा, अन्यथा हर साल पराली, पंजाब-हरियाणा के किसान, धुंध, स्माग आदि की गूंज अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक सुनाई पड़ती रहेगी और बाद में सन्नाटा पसर जाएगा।

प्रोफेसर मान सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

सनातन संस्कृति पर हमले

सनातन संस्कृति के किसी भी सार्वजनिक उत्सव पर बार-बार पथराव-आक्रमण करने के लिए एक वर्ग अभ्यस्त हो गया है। हमारा प्रशासन सदा उन्हें अराजक तत्व या समुदाय विशेष के कुछ लोग कहता है। सनातन धर्म सदा से सहनशील समाज है, अपितु कभी-कभी क्रिया की प्रतिक्रिया भी आ जाती है। विज्ञान का सिद्धांत है कि किसी भी गेंद या ठोस पत्थर को आप सामने की दीवार पर जोर से पटक कर मारेंगे तो तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप वह वस्तु आपकी तरफ वापस आएगी। सनातन संस्कृति की सभी उत्सवों-शोभायात्राओं में आयोजकों को सुरक्षा के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करनी चाहिए।

सुधीर गोयल, हापुड़

जागरूकता से रुकेगा पराली का जलना

पराली को बिना जलाए इसके निपटान की तकनीक सामने आई है। इसमें नाम-मात्र का खर्च आता है। अपघटक नामक तकनीक में अपघटक कैप्सूल और आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री का उपयोग करके तरल मिश्रण तैयार किया जाता है। फसल अपशिष्ट पर इसका छिड़काव किया जाता है। इस तकनीक से उर्वरकों के उपयोग में कमी आने के साथ-साथ खेतों में मृदा की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। चार कैप्सूल का उपयोग कर गुड़ और चने के आटे से किसान लगभग 25 लीटर तरल मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जो एक हेक्टेयर भूमि पर छिड़काव के लिये पर्याप्त है। जब किसान फसल अपशिष्ट या पराली पर इस तरल मिश्रण का छिड़काव करता है तो फसल अपशिष्ट नरम होकर पिघल जाती है। बिना फसल अपशिष्ट को जलाए किसान फिर से बोआई कर सकते हैं। इस तकनीक से मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होता है, क्योंकि जैव-अपघटित होकर यही अपशिष्ट फसलों के लिए खाद का काम करता है। इससे उर्वरकों की कम खपत की आवश्यकता होगी।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा सेक्टर-10, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43566300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

शंघाई सहयोग संगठन

जयशंकर का संदेश

शंघाई सहयोग संगठन-एससीआई के इस्लामाबाद में आयोजित हालिया सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद से निपटने की आवश्कता रेखांकित करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में 'विश्वास में कमी' की बात कही। उनका संबोधन शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के चार्टर में रेखांकित सिद्धान्तों को केन्द्र में रखते हुए था। जयशंकर ने अपने संबोधन में में वास्तविक सहयोग की आवश्यकता, संप्रभुता का सम्मान तथा आतंकवाद, अतिवाद व अलगाववाद की 'तीन बुराइयों' के खिलाफ अडिग दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंध बहुत खराब स्थिति में हैं। विदेश मंत्री ने विश्वास के वर्तमान संकट की ओर इशारा करते हुए कहा, 'यदि विश्वास में कमी है या सहयोग काफी नहीं है, यदि मित्रता में कमी आई है तथा अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब हो गई है तो निश्चित रूप से आत्ममूल्यांकन तथा कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता है।' उनके कथन का संबंध चीन द्वारा एकपक्षीय रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किए जाने वाले सीमा उल्लंघनों तथा पाकिस्तान द्वारा सीमापार से आतंक को राज्य-नीति का अंग बनाने से है। जयशंकर के संबोधन का मुख्य बिंदु आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के खिलाफ तत्काल संघर्ष का रहा जिनको उन्होंने 'तीन बुराइयों' का नाम दिया। उनके अनुसार ये तीनों बुराइयां इस क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल गई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इन बुराइयों के कारण शांति और स्थायित्व को खतरा पैदा होता है जो विकास की पूर्व शर्त हैं। इन मुद्दों को संबोधित किए बिना आर्थिक वृद्धि, व्यापार, कनेक्टिविटी तथा जनता से जनता का संवाद ठीक से विकसित नहीं हो सकेंगे। इस्लामाबाद सम्मेलन में जयशंकर की सहभागिता भारत की राजनयिक रणनीति में महत्वपूर्ण क्षण है।

तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद उनके भाषण से संकेत मिलता है कि भारत पड़ोसियों के साथ संवाद के लिए तैयार है, बशर्ते कि विश्वास और सुरक्षा सबंधी सभी मूल मुद्दों को संबोधित किया जाए। इस सम्मेलन ने दिखा दिया कि क्षेत्रीय व्यवहार की भारत की उम्मीदों तथा उसके कुछ पड़ोसियों द्वारा अपनाई नीतियों के बीच खाई बढ़ रही है। देखना होगा कि चीन और पाकिस्तान जयशंकर की टिप्पणियों पर आत्मावलोकन करते हैं या उन नीतियों को जारी रखते हैं जिनसे क्षेत्र में क्षेत्रीय समन्वय में बाधा आती है। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि ऐसी कार्रवाइयों के माध्यम से विश्वास बहाली की जानी चाहिए जो सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को सम्मान देती हों। अब जिम्मेदारी पड़ोसियों की है कि वे शांति और स्थायित्व के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। अपने संबोधन में जयशंकर ने एससीओ मंच का प्रभावी उपयोग कर चीन के सीमा उल्लंघनों तथा पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद प्रायोजन को 'आईना दिखा दिया' है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस्लामाबाद एससीओ सम्मेलन में कहे गए शब्द न केवल आलोचना का काम करते हैं, बल्कि वे एससीओ चार्टर में उल्लिखित सिद्धान्तों के प्रति पुन: प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। इससे शांति तथा अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का अडिग दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। अब देखना होगा कि चीन व पाकिस्तान के नेता यह भावना समझ कर इसके अनुकूल आचरण करते हैं अथवा यह क्षेत्र अविश्वास व असहमति से परिभाषित यथास्थिति में फंसा रहेगा।

शहरी संस्थाओं का सशक्तीकरण

अपने आर्थिक महत्व के बावजूद अधिकांश शहरी क्षेत्र जलवायु संकट के बढ़ते खतरों के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं। शहरी स्थानीय संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से संघर्ष हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

सोनल सिंह
(लेखिका, टीईआरआई में रिसर्च असोसिएट हैं)

हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने न केवल पार्टी के उभार का विमर्श ठंडा कर दिया है, बल्कि इसने गठबंधन राजनीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता भी उजागर की है। हरियाणा में पराजय के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 'इंडिया' गठबंधन में सहयोगियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने हालिया हरियाणा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके कारण दस साल सत्ता में रहने के कारण पैदा 'सत्ता-विरोधी भावनाओं' के बावजूद भाजपा को तीसरी बार विजय प्राप्त कर सरकार बनाने का अवसर दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अधिकांश एक्जिट पोलों ने कांग्रेस की स्पष्ट विजय का अनुमान लगाया था, पर इसके बावजूद भाजपा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 48 जीतने में सफल हुई।

भाजपा की इस भारी विजय का अनुमान संभवत: पार्टी नेताओं को भी नहीं था। यदि हरियाणा में कांग्रेस एक्जिट पोल अनुमानों के अनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल होती तो इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में उत्साह पैदा होता तथा देश भर में उसकी छवि में और व्यापक सुधार होता। लेकिन इसके एकदम विपरीत कांग्रेस हाल में अपने आंतरिक टकरावों के कारण पांचवां विधानसभा चुनाव हार गई है। इसके पहले वह पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देख चुकी है।

कांग्रेस की हरियाणा में इस पराजय से अब यह निश्चित नहीं है कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी भविष्य में भाजपा के खिलाफ मुकाबले के लिए एकजुट होंगे। ऐसे में बहस हो रही है कि यदि कांग्रेस का हरियाणा में आम आदमी पार्टी-आप से गठबंधन होता तो क्या वह चुनाव जीतने में सफल होती। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति तथा 'इंडिया' के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, हरियाणा में कांग्रेस की पराजय का प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। हरियाणा चुनाव परिणाम का तत्काल प्रभाव आगामी दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा समझौतों पर पड़ सकता है। इन चुनाव परिणामों के बाद आप ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा ही कर दी है।

तीसरा, यह अनिश्चित है कि क्या कांग्रेस और आप का भविष्य में कोई गठबंधन होगा क्योंकि आप ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अपने लचीलेपन तथा सुलह-समझौते की नीति के कारण 'इंडिया' ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारना था ताकि भाजपा-विरोधी वोटों में विभाजन को रोका जा सके। गठबंधन ने विवादास्पद मुद्दों को पीछे छोड़ कर अपने कामकाज में अच्छा प्रबंधन किया था। 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों ने मोटेतौर से भाजपा को हराने का लक्ष्य सामने रखा था और वे एक सीमा तक सफल भी हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहुमत घटा और वह जदयू व टीडीपी की सहायता से ही सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने गठबंधन के भीतर स्थिति एकदम बदल दी है। इस पराजय के कारण अब 'इंडिया' में गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस पर बढ़त मिल गई है। गठबंधन सहयोगी अब संभवत: ज्यादा कठोर दृष्टिकोण अपनायेंगे जिससे कांग्रेस को झुकने पर मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, अब तक किसी ने यह नहीं कहा है कि 'इंडिया' गठबंधन समाप्त हो गया है।

इसके उलट परिणाम आने के अगले दिन समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने अपने बयान से संकेत दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया समूह बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा।' लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी-आप ने कहा है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जबकि उसने तीन महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

'इंडिया' समूह में अन्य गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह अति-विश्वास से भरी थी तथा उसने सीट-साझा के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दूनी कर ली थी और वह उत्साह से भरी थी, लेकिन हरियाणा में पराजय के बाद वह कमजोर हुई है और उसे भारी झटका लगा है। अधिकांश एक्जिट पोलों ने हरियाणा में कांग्रेस की शानदार विजय की भविष्यवाणी की थी क्योंकि भाजपा दस साल की सत्ता-विरोधी लहर का सामना कर रही थी और जनता का एक हिस्सा उसके कामकाज से निराश था। लेकिन भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से न केवल हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय पाई, बल्कि उसका यह प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। किसी पार्टी ने अब तक इस ग्रामीण-प्रभुत्व वाले राज्य में लगातार तीसरी बार विजय पाई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना-उद्धव तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा के बीच सीट-साझे पर बातचीत जारी है।

हरियाणा में पराजय के बाद कांग्रेस को सीट-साझा फार्मूले के प्रति ज्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए तथा उसे चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित करने की शिवसेना की मांग पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। जहां तक हरियाणा विधानसभा चुनाव का सवाल है, आप को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली और उसे लगभग केवल 1.78 प्रतिशत वोट ही मिले। लेकिन यदि कांग्रेस ने आप से गठबंधन किया होता तो ये वोट निश्चित रूप से 'इंडिया' को मिलते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस ने छोटी पार्टियों तथा उनके द्वारा किए जा रहे गठबंधन प्रयासों को अनदेखा किया। तृणमूल कांग्रेस, आप, शिवसेना-उद्धव, नेशनल कान्फ्रेंस, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा अन्य ने कांग्रेस की आलोचना की है कि वह अपनी गलतियों के कारण हरियाणा में पराजित हुई। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' ने अपने संपादकीय में बुधवार को कहा, 'किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा में भाजपा सरकार फिर आ जाएगी।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अति-आत्मविश्वास तथा स्थानीय कांग्रेस नेताओं का घमंड पार्टी की पराजय का कारण बना।' ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा के लिए लोकसभा चुनाव का फार्मूला दुहराना जरूरी हो गया है। अब अधिकांश सहयोगियों के साथ सीट-साझे में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहेगा। 'इंडिया' गठबंधन में व्याप्त वर्तमान सोच से कांग्रेस के अपने सहयोगियों के साथ संबंध प्रभावित होंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व पराजय से स्पष्ट है कि अब विपक्ष हालिया विधानसभा चुनावों में पराजय के और झटके झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को मुख्यत: उन 286 सीटों पर ही ध्यान देना चाहिए जहां वह भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में संयोग से कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ 'स्ट्राइक रेट' 29 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जबकि यह 2019 में केवल 8 प्रतिशत था। इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में कांग्रेस ने केवल 286 सीटों पर भाजपा से मुकाबला किया, जबकि इन सीटों की संख्या 2014 में 370 थी। कांग्रेस को 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने साझीदारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण ही विजय मिली थी। वर्तमान समय में गठबंधन को व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। उसे यह अवश्य समझना चाहिए कि कोई साझीदार चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके लिए जरूरी है।

कांग्रेस ने अतीत में अनेक 'चिंतन शिविर' आयोजित किए हैं, पंचमढ़ी और शिमला इनके अच्छे उदाहरण है। वर्तमान समय की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित व अभूतपूर्व पराजय के बाद कांग्रेस ऐसा ही एक और चिंतन शिविर आयोजित करे।

व्यापक परिदृष्य को समझना आवश्यक

> सरल शब्दों में कहें तो वृहद परिदृष्य का अर्थ होता है किसी चीज़ को उसकी संपूर्णता में जानना।

अजित कुमार बिश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक शिक्षक हैं)

यह बड़ा परिदृष्य क्या है, जिसका उल्लेख आध्यात्मिक वार्तालापों में मिलता है? सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है किसी चीज़ को उसकी संपूर्णता में जानना। उदाहरण के लिए, हम अपने बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं, यानी हम कौन हैं; हम कहाँ से आए हैं; हम कहां जा रहे हैं; इत्यादि। इन और कई अन्य प्रश्नों का उत्तर तब मिल सकता है जब हम सब कुछ के स्रोत, यानी ईश्वर, जो सब कुछ है, के पास जाएं। (भगवद-गीता 7.19) हम, आत्माएं, उनके अंश हैं (15.15); हम शाश्वत रूप से विद्यमान हैं; हम वर्तमान में भौतिक शरीर में हैं।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम केवल उसी के योग्य थे। स्वर्ग जैसे श्रेष्ठ ग्रह हैं और निश्चित रूप से, वैकुंठ - ईश्वर का ग्रह (15.6)। हमारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है? यह पूरी तरह से कर्मों (हमारे कर्मों) पर आधारित है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। हममें से अधिकांश लोग मुख्य रूप से भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं।

हम कभी-कभार मंदिर जाना, आध्यात्मिक चर्चा सुनना आदि जैसे आध्यात्मिक कार्यों का थोड़ा प्रतिशत कर सकते हैं। ये सभी उच्चतम ग्रह, यानी वैकुंठ जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

हम पृथ्वी ग्रह पर जन्म लेते रहते हैं और कभी-कभार स्वर्ग जाते हैं। इन सब में भगवान की क्या भूमिका है? भगवान हम जो कुछ भी देखते हैं, उसके निर्माता हैं; वे इसके नियंत्रक भी हैं। तार्किक रूप से, भगवान को बड़ी तस्वीर पता होनी चाहिए। वे जानते हैं; भगवान सर्वज्ञ हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को भी जानते हैं। जिस तरह हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल का परिणाम है, उसी तरह हमारा भविष्य हमारे वर्तमान का परिणाम होगा।

भगवान जानते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कैसे करेंगे क्योंकि यह हमारे स्वभाव से प्रभावित होता है - हमारे भाग्य का हिस्सा। चूंकि सृष्टि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण का प्रयोग किया जाना चाहिए। भगवान ऐसा करते हैं। वे अपनी सहायता के लिए दिव्य प्राधिकरण का उपयोग करते हैं; यह उनके पर्यवेक्षण के तहत काम करता है। (9.10) वे बदले में हमारे कर्म के आधार पर हमें पुरस्कृत और दंडित करते हैं। संयोग जैसा कुछ नहीं है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है। संक्षेप में, नियंत्रण के तीन स्तर हैं। ईश्वर मुखिया है। फिर दिव्य सत्ता आती है और अंत में, यह भौतिक प्रकृति है, जिसे ईश्वर ने गतिमान किया है। इसी तरह हमारे पास मौसम, बारिश आदि होते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। हमारे सभी कार्य 'युक्त' होने चाहिए, यानी 'धर्म' के रूप में जाने जाने वाले सर्वोच्च सिद्धांतों के अनुसार उचित। ये नियम स्वयं ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। हमारी आत्मा के विस्तृत विवरण और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम ईश्वर से कैसे मदद ले सकते हैं, इसके बिना बड़ी तस्वीर पूरी नहीं होगी। हम बहुत हैं, पृथ्वी ग्रह पर ही आठ अरब से अधिक।

निश्चित रूप से, हम छोटे हैं और हमें हर समय मदद की जरूरत है, खासकर ईश्वर से, जो केवल बड़ी तस्वीर को जानता है। वर्तमान जीवनकाल समाप्त होने के बाद हम स्थानांतरित हो जाते हैं, जो कि पूर्वनिर्धारित है। जीवन की गुणवत्ता हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

दुर्भाग्य से, हम इसे भौतिक वस्तुओं से चाहते हैं, जो कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए ताकि बदले में दूसरे हमारी सेवा करें। हम अपने जीवन की गुणवत्ता कैसे सुधार सकते हैं? हमें वास्तविकता को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए। यहीं से हमारे जीवन में बड़ी तस्वीर प्रवेश करती है, जो कुछ भी हम अपनी सीमाओं के साथ जान सकते हैं।

इसमें ब्रह्मांडीय डिजाइन को स्वीकार करना और ईश्वर और उसकी व्यवस्था में विश्वास रखना शामिल है। हमें जो कुछ भी करना है, उसमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए; हम आम तौर पर जानते हैं कि वह क्या है। हमें दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए, अन्यथा दुनिया को हमारा कोई उपयोग नहीं होगा। हमें सहनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन यह एक एकाग्रता शिविर भी नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन काफी अच्छा हो सकता है।

आप की बात

सैनी का शपथग्रहण

मीडिया में आ रही तमाम आशंकाओं, संभावनाओं एवं अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए महर्षि वाल्मीकि जयंती दिवस पर नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा में पदभार ग्रहण कर यथासंभव संतुलित मंत्रिमंडल बनाया है। जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए इसमें महिलाओं को भी समुचित स्थान दिया गया है। अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व रूप से हरियाणा में राज्य गठन के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली नवनिर्वाचित भाजपा सरकार से जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। भाजपा की इस उपलब्धि के पीछे पिछले दो कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में उसका शानदार काम रहा है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस संबंध में यह कथन उल्लेखनीय है कि प्रत्येक गांव को पिछले दस साल में कम से कम आठ करोड़ रुपये की विकास परियोजनायें मिली हैं। हरियाणा के इतिहास का यह परिवर्तनकारी मोड़ इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति आयाराम-गयाराम परिपटना के कारण बदनामी की शिकार रही है। नायब सिंह सैनी सरकार के समक्ष अवसर है कि वे पूरे देश और दुनिया के सामने ग्रामीण व शहरी विकास तथा जन-कल्याण में सामंजस्य बैठाने का माडल पेश करने का प्रयास करें।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

असम एकार्ड को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6.। की संवैधानिकता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की समस्या को देखते हुए दो कटऑफडेट रखना सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालतों को नागरिकता संबंधी मामलों को निपटाने में पूरी सहायता मिलेगी साथ ही साथ ही इससे संबंधित संस्थाएं भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के हिसाब से निर्णय ले सकेंगी। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने असम एकार्ड को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला भारत में अवैध घुसपैठियों के प्रति कठोर दृष्टिकोण भी व्यक्त करता है। वास्तव में पूर्व पूर्वी-पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भारत के लिए समस्या रही है। कुछ निहित स्वार्थी नेताओं ने अपने संकुचित दलगत स्वार्थों के लिए ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इन अवैध घुसपैठियों ने भारतीय जनता के संसाधनों पर गलत ढंग से कब्जा किया। कोई भी संप्रभु देश ऐसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। असम समझौते पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा कर भारत की एकता-अखंडता को मजबूत किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला दूरगामी सिद्ध होगा।

- सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

न्याय की नई देवी

अंग्रेजों के जमाने से स्थापित न्याय की देवी की मूर्ति की आँखों से पट्टी तथा हाथ से तलवार प्रधान न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हटा दी गई है। अब न्याय की देवी की आंखें खुली रहेंगी और बाएं हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान की पुस्तक होगी। दोनों पक्षों को बराबर सुनने की प्रतीक तराजू उसके दाहिने हाथ में पहले की तरह है। न्याय की देवी की मूर्ति में किया गया बदलाव भारतीयता के अनुरूप बताया जा रहा है। हालांकि, संविधान की व्याख्या तथा न्याय की देवी की निष्पक्षता पर विवाद उठ सकते हैं। पुराने प्रतीक के पक्ष में भी अनेक लोग रहे हैं। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी का पहले भी मजाक उड़ाया जाता रहा है, लेकिन यह निष्पक्षता का प्रतीक भी रही है। तलवार का अर्थ अपराधियों को कठोर दंड देना रहा है, अब उसकी अनुपस्थिति का क्या अर्थ निकाला जाएगा? संविधान की व्याख्या सत्तारूढ़ लोगों की सोच पर निर्भर करती है। बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान का क्रियान्वयन और व्याख्या उसे लागू करने वाले की न्यायप्रियता, विवेक और निष्पक्षता पर निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थितियों में न्याय की नई देवी बहस का विषय बनी रहेंगी।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

कनाडा की राजनीति

कनाडा में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और वहां जस्टिन त्रूदो की सरकार के प्रति स्थानीय जनता की नाराजगी को देखते हुए उसके फिर से सत्ता में आने के कोई आसार नहीं बचे हैं। ऐसे में वे कनाडा में बड़ी संख्या में बसे सिख समुदाय के वोटों के लिए खालिस्तान-समर्थक कनाडाई नागरिकों को शह दे रहे हैं। त्रूदो ने भारत सरकार पर अपने नागरिकों की हत्या के बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अमेरिका के भी कुछ अधिकारी बिना किसी सबूत के भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। अमेरिका भी जानता है कि खालिस्तानियों ने भारत को कई जख्म दिए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या तक में भी खालिस्तान-समर्थक उग्रवादियों का हाथ था। भारत द्वारा कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाना उचित है। कनाडा के साथ पश्चिमी देशों के राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि अब भारत की बाण्डोर मजबूत हाथों में है और वह अकारण किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। उम्मीद है कि कनाडा की जनता आतंकवादी खतरे को समझेगी।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।